● वर्ष-4
● अंक-113
रायपुर, शनिवार
21 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» लूज कपड़ों की इंस्टेंट फिटिंग ...

संभल में खुला कार्तिकेय मंदिर

नईदिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यूपी के संभल में कार्तिकेय मंदिर में कार्बन डेटिंग की है। मंदिर को 46 साल तक बंद रहने के बाद 13 दिसंबर को फिर से खोला गया था। स्थानीय खातों के अनुसार, सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थानीय हिंदू समुदाय विस्थापित हो गया था, जिसके बाद 1978 से मंदिर बंद कर दिया गया था। जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि एएसआई का निरीक्षण सावधानी से किया गया, जिसमें चार सदस्यीय टीम इस प्रक्रिया की निगरानी कर रही थी। अधिकारियों ने कार्बन डेटिंग की और 19 कुओं के निरीक्षण के साथ-साथ भद्रक आश्रम, स्वर्गदीप और चक्रपाणि सहित आसपास के पांच तीर्थ स्थलों की जांच की। एएसआई ने स्थानीय प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि उनकी निरीक्षण गतिविधियां मीडिया की सुर्खियों से दूर रहें। अधिकारियों ने पहले कहा था कि मंदिर की खोज एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई थी। अधिकारियों ने इस खोज को अनियोजित बताया। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) वंदना मिश्रा, जो क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का निरीक्षण करते समय, हमारी नजर इस मंदिर पर पड़ी। इस पर ध्यान देने पर, मैंने तुरंत जिला अधिकारियों को सूचित किया।

मंदिर को दोबारा खोलने के बाद उसके पास एक कुएं की खुदाई के दौरान लगभग चार से छह इंच की तीन मूर्तियां मिलीं। दो देवी पार्वती और लक्ष्मी की प्रतीत होती हैं।

योगी ने सनातन धर्म का सम्मान करने का आह्वान किया

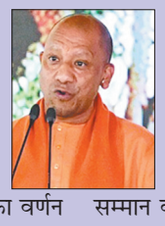

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सशक्त बयान में वैश्विक सभ्यता को संरक्षित करने के लिए सनातन धर्म का सम्मान करने और उसका सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। अयोध्या में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत के ऋषियों ने प्राचीन ज्ञान के बारे में बात की, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम का वर्णन किया गया - पूरे विश्व का एक परिवार। उन्होंने यह भी कहा कि यह धर्म हमेशा अन्य धर्मों और समुदायों के प्रति दयालु रहा है, खासकर संकट के समय उन्हें आश्रय प्रदान करके। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं को ऐसा सम्मान क्यों नहीं दिया गया है।

हाथापाई मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा

नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में धक्कामुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली थी जिसे शुक्रवार को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम मामले की जांच करेगी। यह मामला भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताआ कि हमने मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान दर्ज कर सकती है और गांधी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। बता दें कि बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का-मुक्की भी हुई थी।

संसद मार्ग थाने की टीम शुक्रवार को घायल सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान दर्ज करने राममनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) पहुंची, लेकिन शुक्रवार शाम तक दोनों संसद सदस्य आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस दल को पीड़ित सांसदों के बयान दर्ज किए बिना ही लौटना पड़ा।

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

इस बीच, पुलिस ने कांग्रेस द्वारा दायर एक

शिकायत के जवाब में एक अलग प्राथमिकी दर्ज करने पर कानूनी सलाह मांगी है, जिसमें भाजपा सांसदों पर संसद परिसर में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेताओं की शिकायत को एफआईआर में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

पुलिस कर सकती है सीन रीक्रिएट

राहुल के खिलाफ मामले की जांच के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि पुलिस उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी जहां घटना हुई थी और मीडिया हाउसों से भी संपर्क करके उनके पास मौजूद किसी भी वीडियो सबूत के बारे में पूछताछ करेगी। सूत्र ने कहा कि जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस अपराध स्थल पर फिर से सीन रीक्रिएट करेगी।

भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल ने दावा किया कि खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का-मुक्की की गई, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता। यह संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबासाहेब की स्मृति का अपमान हुआ है।दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह की बाबासाहेब आंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के %मकर द्वार% के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की।

किस बात पर विवाद?

दरअसल, अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में बुधवार से गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने %भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा% विषय पर राज्यसभा में दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबासाहेब का अपमान किया। दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबासाहेब का अपमान किया।

राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल

फडणवीस का खुलासा,काठमांडू में हुई एक बड़ी मीटिंग

नईदिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल संगठन शामिल थे और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रचने के लिए नेपाल में एक बैठक की। विधानसभा में बोलते हुए, फडणवीस ने कहा कि वित्तीय राजधानी में अशांति पैदा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 नवंबर को काठमांडू में बैठक आयोजित की गई थी। फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने चुनावों में आतंकवादी फंड के इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि विदेशी हस्तक्षेप के सबूत हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि 15 नवंबर को, काठमांडू में एक बैठक हुई जिसमें (राहुल गांधी के नेतृत्व वाली) भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले कुछ संगठनों ने भाग लिया और ईवीएम का विरोध, और महाराष्ट्र और भाजपा शासित राज्यों में मतपत्र की शुरूआत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए राहुल गांधी पूरे देश में पदयात्रा पर निकले। फडणवीस ने आगे दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में भाग लेने वाले 180 संगठनों में से 40 को कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल ने फ्रंटल संगठनों के रूप में नामित किया था। उन्होंने आगे कहा कि 18 फरवरी 2014 को, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, केंद्र ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का उल्लेख किया, जिनमें से 7 भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए प्रचार किया। फडणवीस ने कहा कि भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत हैं। विपक्ष अपने कंधों का इस्तेमाल किसी और को करने दे रहा है।

सीएम साय से प्रख्यात अभिनेता और पद्मश्री मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में प्रख्यात अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर छत्तीसगढ़ की माटी में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और अभिनेता श्री जोशी के मध्य छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की संभावनाओं सहित निर्माताओं और फिल्म कलाकारों में छत्तीसगढ़ को लेकर बढ़ती रुचि के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्री जोशी के अभिनेता के रूप में निभाए चर्चित किरदारों की प्रशंसा भी की।

प्रमुख समाचार

शाह और राहुल गांधी पर भड़कीं मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जर्बदस्त हमला बोला हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने भी कहा है कि अमित शाह को उन शब्दों को वापस लेकर पश्चाताप करना चाहिए. इतना ही नहीं मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि जगह-जगह संविधान लहराना और नीले रंग के कपड़े पहनना दिखावे की सस्ती राजनीति है। मायावती ने कहा कि संसद में दलित और उपेक्षित वर्गों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी और उसके सहयोगी पर भड़कते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इनकी चाल, चरित्र और चेहरा बाबा साहेब अंबेडकर और उनके करोड़ों दलित-पिछड़े, शोषित-पीड़ित अनुयाइयों के हित व कल्याण के प्रति हमेशा संकीर्ण, जातिवादी रहने के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात लगातार बदतर हैं।

ओमप्रकाश चौटाला का निधन

नई दिल्ली। अनुभवी इंडियन नेशनल लोकदल नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले चौटाला का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति, चौटाला ने कई अवसरों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें आईएनएलडी में उनके नेतृत्व और राज्य की राजनीतिक दिशा को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हरियाणा के विकास में चौटाला के योगदान को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। चौटाला परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, हालांकि सभी सदस्य इनेलो और जननायक जनता पार्टी के बीच विभाजित हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय, भिवानी के पूर्व सांसद और तीन बार के विधायक को जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पिता के साथ दोषी ठहराया गया था। इनेलो ने पिछली बार 2005 में हरियाणा पर शासन किया था।

राम रहीम पर उच्च न्यायालय में फिर चलेगा केस

चंडीगढ़। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साधुओं को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर नपुंसक बनाने के मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़े मामले की केस डायरी डेरा मुखी को सौंपने के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामला दोबारा सीबीआई स्पेशल कोर्ट को भेजते हुए नए सिरे से इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। सीबीआई ने 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को अपना बचाव तैयार करने के लिए यह केस डायरी, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने ही डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर हाईकोर्ट में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दे दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में डेरा मुखी की एक अर्जी पर इस मामले की केस डायरी उसे सौंपने का सीबीआई को आदेश दिया था।

भाजपा के संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सभी 70 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। प्रत्येक सीट पर दो से चार दावेदारों के नाम शामिल किए गए हैं। पार्टी की चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के चयन में कई प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखा है। इनमें विरोधी दलों के कद्दावर उम्मीदवारों को घेरने, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास प्रमुख है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के घोषित और कांग्रेस के घोषित व संभावित उम्मीदवारों का गहन आकलन किया है। आप के प्रमुख उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए भाजपा ने रणनीतिक रूप से उनके खिलाफ प्रभावशाली उम्मीदवारों को खड़ा करने की योजना बनाई है। इसी तरह, कांग्रेस के 21 घोषित और 49 संभावित उम्मीदवारों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी अध्ययन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने कई सीटों पर ऐसे नेताओं को पैनल में शामिल नहीं किया है, जिनकी जाति विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों से मेल खाती हो। इसके बजाय, भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवार स्थानीय जनाधार, जातीय समीकरण और प्रभावशाली छवि के आधार पर चुने जाएं।

राज्यसभा में भी एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी गठित

नई दिल्ली। बारह राज्यसभा सदस्यों को संयुक्त संसदीय समिति में नियुक्त किया गया है, जिन्हें एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल पर विचार-विमर्श करने का काम सौंपा गया है। इस सूची में घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के. लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, साकेत गोखले, पी. विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मंगराज और वी विजयसाई जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का मामला आपराधिक कानून के प्रावधानों का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने एएनआई से कहा कि बुनियादी बात यह है कि जिन लोगों ने जाने-अनजाने में भारतीय संविधान के संस्थापक डॉ. बाबासेह भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना , मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के एक-एक सदस्य के अलावा भाजपा पार्टी (भाजपा) के दो और समाजवादी पार्टी का एक और सदस्य शामिल है। सदन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव है।

हसीना को हटाया, यूनुस का मास्टरमाइंड कहलाया महफूज आलम

कीर्तिवर्धन मिश्र

बांग्लादेश में छात्रों के उग्र प्रदर्शनों के बीच 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब तक बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार के खिलाफ हुई इस क्रांति के पीछे छात्रों के संगठनों की सबसे अहम भूमिका मानी जा रही थी। हालांकि, अब बांग्लादेश में एक नाम तेजी से उभरा है, जिसे खुद देश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हसीना सरकार को हटाने का मास्टरमाइंड तक कह दिया। इस छात्र नेता का नाम है महफूज आलम, जिसके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में भी दरार डालने का काम किया है। उसकी इस हरकत के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को फटकार लगाई है।

महफूज आलम जिसे महफूज अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है की पहचान बांग्लादेश में छात्र कार्यकर्ता की है। उसे कई सामाजिक आंदोलनों में हिस्सेदारी लेने के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही महफूज आलम कुछ ऐसे तत्वों के संपर्क में आया, जो कि आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर (एचयूटी) से जुड़े थे।

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। प्रदर्शन की शुरुआत तो आरक्षण को लेकर हुई थी, लेकिन देखते हर देखते इसने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। इन्हीं प्रदर्शनों में बाद में छात्र संगठन भी जुड़ गए। विरोध कर रहे छात्रों के समूह ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल जमा नहीं करने की अपील की।

छात्रों ने कारखानों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया।

कुछ ही समय में यह प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि प्रदर्शनों के बीच हिंसा शुरू हो गई। इन हिंसा की घटनाओं में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आईं। इतना ही नहीं शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बावजूद हिंसा की कई घटनाएं सामने आती रहीं। इनमें अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को निशाना बनाने के कई मामले भी सामने आए।

बताया जाता है कि छात्र संगठनों का शेख हसीना की सरकार के खिलाफ यह आंदोलन महफूज आलम के नेतृत्व में ही शुरू हुआ। बांग्लादेश में तब महफूज आलम को छात्रों के मार्गदर्शक के तौर पर भी जाना गया। हालांकि, शेख हसीना को हटाने में उसकी भूमिका का खुलासा पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में किया।

मोहम्मद यूनुस हाल ही में अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के इतर न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनीशिएटिव से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उनके साथ महफूज आलम की भी मौजूदगी रही। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने महफूज को शेख हसीना को हटाने वाले छात्र आंदोलन के पीछे का %दिमाग% करार दिया था। यूनुस ने कहा था कि छात्रों की यह क्रांति सावधानीपूर्वक डिजायन की गई थी।

यूनुस ने महफूज आलम की तरफ इशारा करते हुए कहा था, ये पूरी क्रांति के पीछे का दिमाग हैं। ये (महफूज आलम) लगातार इस बात से इनकार करता है, कि ये मैंने नहीं काफी और लोगों ने किया है। लेकिन इस पूरी चीज के पीछे इन्हीं का दिमाग है। यह सावधानीपूर्वक डिजायन की गई चीज। यह अचानक से ही नहीं हुई। इसे (छात्र आंदोलन) को काफी अच्छी तरह से डिजायन किया गया था। आप पहचान नहीं सकते थे कि इसका (क्रांति का) नेता कौन है। इसलिए वह (हसीना सरकार) किसी एक को पकड़कर यह नहीं कह सकते कि अब खेल खत्म।

आलम के पोस्ट को लेकर विवाद

प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा करने वाले महफूज आलम को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार में सलाहकार की भूमिका दी है। वह एक मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है। इन पदों पर होने के बावजूद उसने हाल ही में एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसे लेकर भारत की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। अपने पोस्ट में महफूज आलम ने लिखा कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में लोगों की संस्कृति धर्म से इतर 'एक जैसी' है। उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण हुआ।

महफूज आलम ने इसी पोस्ट में दावा किया, भारत ने एक नियंत्रण और यहूदी बस्ती कार्यक्रम अपनाया है। भारत से सच्ची आजादी सुनिश्चित करने के लिए, हमें 1975 (शेख मुजीब उर-रहमान की हत्या का घटनाक्रम) और 2024 (शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़कर भागने का घटनाक्रम) को दोहराना होगा। आलम ने कहा कि दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है।

मनेंद्रगढ़ नगरपालिका में आरक्षण विवाद

कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने आरोपों को बताया राजनीतिक

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ नगरपालिका के 22 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई ।लेकिन आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं ।जहां एक ओर कांग्रेस आरक्षण की प्रक्रिया को गलत बता रहा है,वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आरक्षण में नियमों का पालन किया गया है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ। विनय जायसवाल ने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विनय जायसवाल ने आरोप लगाए कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को न केवल नजरअंदाज किया गया है, बल्कि आरक्षण प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं

पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने कहा राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए थे, वे केवल कागजों तक सीमित हैं ।मनेंद्रगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या 40 प्रतिशत है। यहां केवल नौ सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी। सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी कर नाटक किया है। जो सरकार पिछड़े वर्ग की बात करती है, उसने केवल दिखावा किया ।आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है।

वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक के आरोपों को एक सिरे से नकारा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी के मुताबिक विनय जायसवाल का बयान राजनीति से प्रेरित है।

अनिल केशरवानी ने कहा कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है ।मनेंद्रगढ़ नगर पालिका आरक्षण की प्रक्रिया पहले भी हुई थी और उसे प्रावधानों के तहत पूरा किया गया था। कांग्रेस के नेता बेवजह मुद्दे को तूल देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर स्थान को राजनीतिक अखाड़ा बनाना हास्यास्पद है ।कांग्रेस के आरोप केवल राजनीतिक फायदे के लिए किए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि 17 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान मनेंद्रगढ़ नगरपालिका को लेकर हंगामा हुआ था ।जिस पर प्रशासन ने पार्षदों को आश्वासन दिया था कि नियमों के तहत ही आरक्षण लागू किया जाएगा ।वहीं जब 19 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई तो कांग्रेस ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की ।लेकिन इस बार प्रशासन ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की ।वहीं अब आरक्षित वार्डों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं।

आरबीआई की मंजूरी के बाद भी सीनपाली में नहीं खुली बैंक शाखा

किसान हो रहे परेशान, बढ़ी पंजीकृत किसानों की संख्या

गरियाबंद। देवभोग विकासखंड के ग्राम सीनपाली में नई बैंक शाखा नहीं खुलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को रोजाना पांच करोड़ की धान खरीदी पर केवल एक करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। देवभोग जिला सहकारी बैंक में बीते दिन कैश की किल्लत के चलते भुगतान नहीं हो सका। ऐसा ही हाल गोहरापदर सहकारी बैंक में भी देखने को मिला है।

देवभोग जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत 10 खरीदी केंद्र आते है। जहां 94 गांव के 9780 किसान धान बेचते हैं। रोजाना 1 हजार किसान, 4 से 5 करोड़ का धान बेचते हैं, कर्ज कटौती के बावजूद बैंक से कम से कम 3 करोड़ का भुगतान किसानों को लेना होता है। लेकिन बैंकों में 1 करोड़ का भुगतान होते होते पूरा दिन निकल जाता है। कैश किल्लत के चलते देवभोग में बुधवार को भुगतान नहीं हो सका, अगले दिन भी बैंक किसानों से भर गया। वहीं गोहरापदर सहकारी बैंक में भी भुगतान को लेकर किल्लत हैं।

2020 में देवभोग ब्रांच के पंजीकृत कृषकों की संख्या 6 हजार से कम थी, जो पिछले चार सालों में 30 फीसदी बढ़कर 9700 के पार हो चुकी है। सरकार के किसान हितैषी फैसले और योजनाओं के बाद सहकारिता बैंक पर किसानों की निर्भरता बढ़ गई। बैंकों को समय के साथ अपग्रेड नहीं करने से एमएसपी योजना से जुड़े कृषकों को भुगतान के दौरान परेशानी हो रही है।

दरअसल, प्रदेश की पिछली भूपेश सरकार ने 6 दिसंबर 2022 को सीनपाली में सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की थी। इससे देवभोग सहकारिता बैंक से 12 पंचायत से जुड़े 30 से भी ज्यादा गांव का भार कम हो जाता। जिला सहकारी बैंक रायपुर कार्यालय ने 30 जुलाई 2024 को गोहरापदर ब्रांच को पत्र लिखा था। जिसमें आरबीआई से मिली मंजूरी का हवाला देकर स्थल चयन का निर्देश दिया। चयन प्रक्रिया पूरी भी हो गई थी, लेकिन प्रकिया को अचानक शिथिल कर दिया गया। किसानों में आक्रोश है, नई बैंक शाखा नहीं खोले जाने पर वे प्रदर्शन की तैयारी में हैं।

मामले में जिला सहकारी बैंक रायपुर की सीईओ अपेक्षा व्यास ने कहा कि तब स्टाफ की कमी थी, अब भर्ती हो गई है। आर बी आई को दोबारा पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है। जल्द ही प्रकिया को शुरू कर दिया जाएगा।

भुगतान की समस्या को लेकर सीईओ अपेक्षा व्यास ने कहा कि प्रत्येक ब्रांच में एटीएम, कई खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम खोली गई है। यूपीआई और ऑन लाइन बैंकिंग से भुगतान की प्रकिया का भी प्रावधान है। जगह-जगह शिविर लगाकर कृषकों को इन भुगतान पद्धति से अवगत भी कराया जा रहा है।

जशपुर में जतरा मेला आयोजन स्थल को लेकर हंगामा, 28 लाख से ज्यादा में नीलामी

जशपुर। पारंपरिक जतरा मेला के आयोजन स्थल को लेकर जशपुर नगर पालिका परिषद में नीलामी प्रक्रिया के दौरान हंगामा और विवाद की स्थिति बन गई। बोली लगाने आए ठेकेदार आयोजन स्थल निर्धारित करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की बता रहे थे। शुरुआत में ही बोलीदारों ने पालिका के अधिकारियों से आयोजन स्थल स्पष्ट करने का अनुरोध किया। गौ शाला समिति की ओर से आए प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें जमीन किराया के रूप में निर्धारित राशि देनी होगी, तभी वे आयोजन की अनुमति देगें।

28 लाख से ज्यादा में जतरा मेला आयोजन स्थल की नीलामी- हंगामे के बीच आयोजित हुई नीलामी में 28 लाख 25 हजार की अधिकतम बोली लगाकर नरेंद्र भगत ने मेला आयोजन का अधिकार हासिल किया। इस सरकारी बोली के अतिरिक्त 7 लाख रुपये ठेकेदार को आयोजन स्थल के भू स्वामी गौशाला समिति को देना होगा। इस तरह मेला का आयोजन 35 लाख 25 हजार रुपये पहुंच गया।

13 लाख से ज्यादा का मिलेगा राजस्व- जतरा मेला के लिए बीते साल 2023-24 की नीलामी राशि 15 लाख 51 हजार रुपये मिली थी। इस साल इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 17 लाख 100 रुपये निर्धारित किया गया। नीलामी प्रक्रिया में 11 बोलीदारों ने भाग लिया। न्यूनतम बोली से शुरू होकर 28 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंची। इस तरह नगर पालिका को बीते साल की तुलना में जतरा मेला के आयोजन से 13 लाख से ज्यादा का राजस्व मिलेगा।

जशपुर नगर पालिका के सीएमओ योगेश्वर उपाध्याय ने बताया कि अधिकतम बोली की राशि को संबंधित ठेकेदार को 24 घंटे के अंदर नगरपालिका में कैश जमा कराना होगा। चूक होने पर अधिकतम दो बोलीदारों को मौका दिया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि सरकारी बोली की राशि से किसी को भी राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। आखिर में अधिकतम बोली के अतिरिक्त गौ शाला समिति को निर्धारित जमीन किराया देने पर सहमति बनी और इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई।

कर्ज में डूबा निगम, गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल के लिए पैसे नहीं

विपक्षी पार्षदों ने कहा- इतने ज्यादा कर्ज से छवि हो रही खराब

धमतरी। धमतरी नगर निगम पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पेट्रोल-डीजल के 20 लाख रुपए से अधिक के कर्ज में नगर निगम डूबा हुआ है। जिसके चलते कई महीनो से पेट्रोल पंप संचालक को भुगतान नहीं हो पाया है। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्षद लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं।

धमतरी निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा का कहना है कि इतनी ज्यादा कर्ज और उधारी से निगम की छवि लगातार खराब होती जा रही है। सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि अलग-अलग विकास कार्य के ठेकेदारों को भी लंबा चौड़ा भुगतान करना बाकी है।

वहीं धमतरी नगर निगम की कमिश्नर ने बताया कि फंडिंग की कमी होने के कारण इतनी ज्यादा कर्ज की स्थिति बनी है। धमतरी निगम अपने आय के स्त्रोतों का अध्ययन कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस भारी कर्ज के बोझ से मुक्ति पाई जा सके।

बता दें कि 40 वार्ड के 2 लाख लोगों के लिए धमतरी नगर निगम पानी, बिजली, साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए चार जेसीबी सहित 50 वाहन का इस्तेमाल करता है। टैक्स वसूली में कमजोर, राशियों के व्यवस्थापन और उपयोग में असफल होने से धमतरी नगर निगम शुरूआत से ही सरकार पर निर्भर रहता है। लेकिन खराब प्रबंधन के चलते सीधा प्रभाव जनता पर ही पड़ता है।

भिलाई मैत्री बाग में सोलर प्लांट की स्थापना हर महीने लगभग 2 लाख रुपये की बचत

भिलाई। मैत्री गार्डन में इस्पात संयंत्र के ग्रिड से जुड़े और ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति के लिए बीएसपी 200 किलोवॉट क्षमता का राज्य का पहला एलिवेटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसकी स्थापना व कमीशनिंग का काम शुरू किया जा चुका है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को एलिवेटेड मॉडल के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है कि इसके नीचे की जमीन का उपयोग जानवरों के लिए चारा उत्पादन में किया जा सकेगा। परियोजना से प्राप्त बिजली का उपयोग मैत्रीबाग व निकटवर्ती जवाहर उद्यान में किया जाएगा।

सौर संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। इसके सामने की ऊंचाई 3 ।5 मीटर है जो जमीन से 5 ।5 मीटर की ऊंचाई तक पीछे की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती है। इस ऊंचाई को प्राप्त करने व पूरे ढांचे की स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है।

इसका वजन करीब 30 टन है जो 200 किलोवॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे भारी सौर संरचनाओं में से एक है। सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिमाह 24000 यूनिट बिजली व न्यूनतम 2,88,000 यूनिट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष करेगा। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बाद मैत्रीबाग को प्रति माह 2 लाख रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही यह सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन 250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाएगा।

मैत्री बाग प्रभारी एनके जैन ने बताया कि बीएसपी के सीएसआर मद से मैत्री गार्डन के जमीन पर 450 द्म1 का सोलर प्लांट का स्थापित किया जा रहा है। मैत्री गार्डन में बिजली की आपूर्ति सोलर प्लांट से ही की जाएगी। इस परियोजना को जनवरी तक पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है। यह परियोजना हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी। हरित ऊर्जा के उत्पादन से वायुमंडल में जहरीली ग्रीनहाउस गैसें नहीं निकलती हैं। इससे पर्यावरण पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल

नारायणपुर। नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा लगाई आईईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जवान कच्चपाल से तोके सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया है। कोहकामेटा थाना इलाके की घटना है। एसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टी की है। जानकारी के मुताबिक, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के कच्चापाल में पुलिस ने बेस कैंप दो दिन पूर्व खोला था और कैंप तक पहुंच मार्ग बनाने में डीआरजी के जवान लगे हुए थे। इसी बीच नक्सलियों ने आईईडी बम लगा दिया, सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवान इसकी चपेट में आ गए। जिसमें दो जवान घायल हो गए। एक जवान के पैर में गंभीर चोट आई है। जिन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नारायणपुर जिला अस्पताल में लाया गया। जहां जवानों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा । घटना की पुष्टि एसपी प्रभात कुमार ने की है। घायल जवानों के नाम घासीराम और जनक पटेल है।

घायल हाथी का इलाज करने कोरबा पहुंची डॉक्टरों की टीम

कोरबा। करतला वन मण्डल के जंगल से गांव में घुसे घायल हाथी के उपचार के लिए रायपुर से मेडिकल टीम कोरबा पहुंची है। जंगल सफारी रायपुर से पहुंची डॉक्टरों की टीम घायल हाथी को ट्रैक्यूलाइज कर इलाज कर रही है। आंख में काला कपड़ा डालकर इलाज किया जा रहा है। हाथी के पेट मे चोट के निशान है, धाव हो जाने के कारण वो चल नही पा रहा है। मौके पर कोरबा डीएफओ अरविंद पीएम और अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। करतला वन मण्डल में जंगल से घायल हाथी गांव के अंदर घुस गया था। जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इक्कठा हो गई थी। जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। एसडीओ सोनी एस के सोनी ने बताया कि चार दिनों तक हाथी पर निगरानी कर ईलाज किया जाएगा। वहीं इस इलाके में 15 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, उनकी भी निगरानी की जा रही है।

डोंगरगढ़ मेले में दुकान आबंटन में भ्रष्टाचार

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां बमलेश्वरी धाम, डोंगरगढ़ में क्वांर नवरात्र मेला के दौरान व्यापारियों को दुकान आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। जांच में नगर पालिका के सीएमओ की संलिप्तता पाई गई है। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से जिला प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर डोंगरगढ़ में वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं। लेकिन, पिछले नवरात्र में इन दुकानों के किराए और बिजली शुल्क के नाम पर भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जांच के बाद एसडीएम डोंगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि नगर पालिका के सीएमओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दुकान आवंटन प्रक्रिया में हेरफेर किया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। मामले में एसडीएम मनोज मरकाम ने कहा कि जांच में अनियमितता पाई गई थी।

पत्नी ने अपना लिया ईसाई धर्म पति ने लगा ली फांसी

बालोद। जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पत्नी के ईसाई धर्म अपनाने और बार-बार विवाद कर मायके जाने से पति आहत था। आत्महत्या से पहले पति ने घर की दिवार पर सुसाइड नोट भी लिखा है। मामले में पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, अर्जुंदा नगर वार्ड क्रमांक 11 के रहने वाले (35 वर्षीय) गजेंद्र देवांगन की पत्नी राजेश्वरी देवांगन ने इसाई धर्म को अपना लिया था। इस बात से पति आहत था। पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। पत्नी बच्चों को छोड़कर बार-बार मायके चली जाती थी। इस बात की जानकारी पति गजेंद्र ने पुलिस थाने में भी 8 दिसंबर को दी थी। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पति गजेंद्र देवांगन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले गजेंद्र ने दिवार पर सुसाइड नोट भी लिखा है। जिसमें पत्नी, सास, ससुर और साले पर गंभीर आरोप लगाया है।

पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। वाड्रफनगर क्षेत्र के मदनपुर गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले के मदनपुर निवासी पति मोहम्मद शमशाद (उम्र 40 वर्ष)जुलेखा बेगम गुरुवार को मदनपुर गांव में रहने वाले दंपत्ति के बीच किसी घरेलू मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने गुस्से में आकर एक-दूसरे पर पेट्रोल डाल दिया और खुद आग लगा ली। उनकी चीख-पुकार सुनकर पास-पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। घटना में पति बुरी तरह से झुलस गया और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पत्नी को भी आग से झुलसने के कारण चोटें आई हैं, लेकिन उसकी स्थिति पति की तुलना में बेहतर है। दंपत्ति को तुरंत वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल ले जाया गया।

हत्या के मामले में आरोपी को भेजा जेल

धमतरी। धमतरी में बीते दिनों हुई एक हत्या का मामला सामने आया था। जिसपर पुलिस हत्या करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई थी ।इस दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ कर 7 दिनों तक पूछताछ की और हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

बताया गया कि तीन दिसंबर 2024 को ग्राम पदमपुर निवासी बीरेंद्र देवांगन उम्र 55 वर्ष की लापता होने की सिहावा थाना में रिपोर्ट दर्च कराई गई थी। वहीं तीन दिसंबर को ही रुद्री पुलिस को एक लावारिस हालात में मोटरसाइकिल खड़ी होने की सूचना मिली थी। जिसपर रुद्री पुलिस मानव वन के पास रोड किनारे खड़ी बाईक को जब्त कर आसपास के जगह की तलाश में जुट गई थी।

पुलिस ने गाड़ी के नंबर प्लेट व अन्य चीज़ों के आधार पर पता तलाश की,जिसमे उक्त बाईक लापता बीरेंद्र देवांगन होना पाया गया ।इस दौरान 6 दिसंबर को रुद्री पुलिस को सूचना मिली कि मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।

पुलिस द्वारा जिसकी पहचान बीरेंद्र देवांगन के रूप में की गई ।वही पुलिस ने शव पंचनामा और पीएम करवाया गया ।जिसके आधार पर उक्त व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया ।जिसपर साइबर और रुद्री पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुखवंत साहू उर्फ़ सुखु निवासी धनोरा जिला दुर्ग को पकड़ा गया ।वही पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से लगातार सात दिनों तक तक पूछताछ करती रही ।जिसपर आरोपी सुखवंत साहू ने अपने दोस्त बीरेंद्र देवांगन को आपसी रंजिश के चलते मौत के घाट उतारना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार रिमांड पर जेल भेज दिया है।

सूरजपुर जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉकड्रिल

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 30 बिस्तर वाले 9 मीटर ऊंचे अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑ़डिट को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान विधायक धरमजीत सिंह ने अस्पतालों के ऑडिट समेत मॉकड्रिल को लेकर सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था। जिसके बाद प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में आगजनी को लेकर मॉकड्रिल हुआ ।इसके बाद अब सूरजपुर जिला अस्पताल में मॉकड्रिल किया गया। अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी की है। जिसे लेकर आगजनी के दौरान विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने सूरजपुर जिला अस्पताल में मॉकड्रिल किया। अस्पताल प्रबंधन सहित कर्मचारियों को आगजनी के दौरान बचाव के तरीके सिखाए।

पूर्व विधायक के पिता पर जानलेवा हमला

- लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी गिरफ्तार

बालोद। बालोद में अहिवारा के पूर्व विधायक राजमहंत सावला राम डाहरे के पिता पर जानलेवा हमला किया गया है। जिसके बाद लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुलाहिजा और प्राथमिक उपचार के बाद दुर्ग रेफर कर दिया गया। पूर्व विधायक के पिता का इलाज किया जा रहा है। मामले में आरोपी कुलदीप डाहरे पिता नेहरू डाहरे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के पिता संत बलदेव साहेब के सिर पर गंभीर चोट आई है। पूरा मामला जिले के रनचिराई थाना क्षेत्र के ग्राम मटिया का बताया जा रहा है।

रनचिराई थाना अंतर्गत ग्राम मटिया में 18 दिसंबर को अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सावला राम डहरे के पिता 92 वर्षीय संत बलदेव साहेब पर गांव के ही आदतन बदमाश कुलदीप डहरे पिता नेहरू डहरे ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संत बलदेव साहेब के सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने रनचिरई थाना में लिखित शिकायत की है। रनचिरई थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि संत बलदेव साहेब कबीर पंथ के साधु ने 2014 में संन्यास ले लिया है ,जो ढाबा कुम्हारी के कबीर आश्रम में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व अपने नाती को देखने गुण्डरदेही ब्लॉक के ग्राम मटिया पहुंचे थे। थाना प्रभारी ने आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। सबूत के आधार पर गुण्डरदेही एसडीएम ने आरोपी को तत्काल जेल भेज दिया।

संक्षिप्त समाचार

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला

रायपुर। एक बार फिर से राज्य सरकार सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तबादला आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव और अवर सचिव लेवल के अधिकारियों को इधर से उधर किया है। संयुक्त सचिव विमला नावरिया को पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग से हटाकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ किया गया है। वहीं उपसचिव शैलाभ साहू को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

आईपीएस जीपी सिंह ने बहाली के बाद दी ज्वाइनिंग, डीजीपी की रेस हुई रोमांचक

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य के

गृह मंत्रालय द्वारा बहाली आदेश जारी करने के बाद एक दिन बाद आईपीएस जीपी सिंह ने ज्वाइनिंग दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में डीजीपी की रेस भी रोमांचक हो गई है। तमाम बाधाओं के बावजूद इस रेस में एक बार फिर से जीपी सिंह शामिल हो गए हैं। हालांकि, आखिरी निर्णय राज्य सरकार का होगा। गौरतलब है कि, 1994 बैच भापुसे अफसर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। इस प्रस्ताव के बाद केंद्र ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

वरिष्ठ आईएएस सुबोध सिंह ने दी ज्वाइनिंग सीएम सेक्रेटेरिएट में मिल सकती है पोस्टिंग

रायपुर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 97 बैच

के आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग में ज्वाइनिंग दी। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से भी मुलाकात की। सुबोध सिंह वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। हाल ही राज्य सरकार के आग्रह पर डीओपीटी ने उन्हें छत्तीसगढ़ वापसी के लिए कार्यमुक्त किया। उनके साथ हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अमित कटारिया को जल्द ही पोस्टिंग मिलने की संभावना है। इसके साथ ही सचिवों और अफसरों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। बता दें कि सुबोध सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, ऐसे में संभावना इस बात की है कि उन्हें एक बार फिर से सीएम सेक्रेटेरिएट में रखा जाए।

डायबिटीज मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे मुख्य कारण चांवल का सेवन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मधुमेह से पीड़ित

मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले वर्षों में इसका प्रतिशत और बढ़ जाएगा। मधुमेह मरीजों की संख्या बढने के पीछे बहुत सारे अनेक कारण है लेकिन विशेषतौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चांवल खाने वाले लोगों की संख्या अधिक है इस वजह से इसमें इजाफा हो रहा है। यह बातें पत्रकारवार्ता के बाद आरएसएसडीआई की राजकीय इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने कहीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अंचल में डायबिटीज के सर्वाधिक मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे है प्रत्येक गांव में जिनका प्रतिशत लगभग 8 से 11 है और संभावना जताई जा रही है इतना ही नहीं नवजात शिशुओं में भी अब डायबिटीज के लक्षण पाए जा रहे है जिसके चलते आने वाले 2040 तक यह संख्या दोगुनी हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ में हड़ताल खत्म, काम पर लौटे नगरीय निकाय कर्मचारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकायों के कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां, कमांडोज और प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल निःशर्त समाप्त कर काम पर लौट आए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला/पुरूष महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। साव ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशील है। अरुण साव ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए सजग और गंभीर है। अरुण साव ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी विषय और समस्याओं को रखने के लिए हड़ताल या आंदोलन ही उचित माध्यम नहीं है। समस्याओं को रखने के अन्य विकल्प भी हैं। आपके हड़ताल पर जाने से शहरों की महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित होती हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से निकाय चुनाव भी प्रभावित हो सकता था। निकाय चुनाव के दौरान नगरीय निकाय कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वहीं स्वच्छता दीदियों के हड़ताल पर जाने से शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा था। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद नाराज कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर सदन में हंगामा

■ कम भुगतान को लेकर मंत्री बोले किसानों के साथ हुआ अन्याय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर हंगामा हुआ। विधायक के प्रश्न पर मंत्री रामविचार नेताम ने योजना और उसमें हुए भुगतान की जानकारी सदन में दी। इस दौरान नेताम ने आरोप लगाए कि किसानों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया है। बीजेपी विधायक ने सदन में पूछा कि साल 2020-21 की तुलना में साल 2021-22 में किसानों की संख्या में इजाफा हुआ था।लेकिन जो भुगतान योजना के तहत किया गया है,वो पिछले साल की तुलना में कम था,जबकि किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

इस प्रश्न के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में सदन में जानकारी दूंगा।इस योजना में किस तरह से किसानों को छला गया है ये भी बताया जाएगा।तब

की सरकार ने किसानों की हितैषी बनने का जो ढोंग किया था,उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। 2019 से 2022 तक पंजीकृत रकबा और भुगतान की बात करें तो साल 2020 में 5627 करोड़, 2021 में 5553 करोड़ , 2022 में 7005 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने किया। जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसानों की उन्नति के लिए रकबा और उत्पादकता के लिए प्रयास किए हैं। अब तक किसानों को 13288 करोड़ का भुगतान किया है। विष्णुदेव साय की सरकार ने देश भर में क्रांतिकारी निर्णय लिया है। वहीं पेंडिंग बोनस की बात करें तो 3800 मिला करके 17 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को किया है। इस दौरान आशाराम नेताम ने पूछा कि आखिर क्यों रकबा और भुगतान में कमी हुई।जबकि किसानों की संख्या बढ़ी थी।

इसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अध्यक्ष महोदय कमी होने का जो मुख्य कारण था, किसानों का जो खेत होता है।उसमें जो मेढ़ होता है। इनकी सरकार ने उस मेढ़ के रकबे में कटौती करके भुगतान किया है। किसानों के साथ अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया।आज किस मुंह से कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं।

इसके जवाब में विधायक संगीता सिन्हा ने मंत्री रामिवचार को बताया कि आप जो बातें कह रहे हैं वो गलत हैं।आप आरोप लगा रहे हैं।किसी भी तरह के मेढ़ में कटौती करके भुगतान नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने एक दिन में ही 10 हजार करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया है।

इसके बाद बीजेपी विधायक ने सदन को बताया कि साल 2020 और 2021 में जो पंजीकृत किसानों की संख्या थी।वो 2021-22 में 2 लाख 15 हजार 698 हो गई।इधर किसान बढ़े हैं।लेकिन जो भुगतान हुआ है वो कम हुआ है।जो जानकारी निकलकर सामने आई कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी,उसमें किसानों के मेढ़ का रकबा घटाकर भुगतान किया गया।यानी कि जो योजना लाई गई थी वो किसानों के साथ न्याय के लिए नहीं बल्कि अन्याय के लिए लाई गई थी।

इसके बाद जवाब में विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि जो संख्या किसानों की बताई जा रही है वो भूमिहीन और अधिया बोने वाले किसानों की है।ना कि पूरे किसानों की।इसलिए कम से कम भूमिहीन किसानों के साथ आप न्याय किजिए।साथ ही मंत्री महोदय ये भी बताने का कष्ट करें कि आखिरी किस्त में कितनी राशि जारी हुई थी।

इसके जवाब में मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि चौथी किस्त में 1975 करोड़ रुपए की राशि किसानों को जारी की गई। जो तीसरी किस्त 7005 करोड़ रुपए से कम थी। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 17 हजार करोड़ रुपए किसानों को दिया है।यही वजह है कि आज देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट छत्तीसगढ़ में है। यहां सबसे ज्यादा ट्रैक्टर और कार की बिक्री हुई है। मंत्री का जवाब सुनने के बाद कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा करने लगे।कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए थे।लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों का एक रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया।जो आंकड़े सदन में मंत्री जी ने दिए हैं वो भूमिहीन और अधिया किसानों के हैं।इसलिए भुगतान भी कम हुआ।

द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में हुआ पारित

छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है।

सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में

रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।

रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। तीसरे अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है।

660 करोड़ की रिएजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू करेगी जांच

■ स्वास्थ्य मंत्री की सदन में बड़ी घोषणा

रायपुर। सीजीएमएससी द्वारा मोक्षित कार्पोरेशन से की गई 660 करोड़ की रिएजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू जांच करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस संबंध में घोषणा की।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक द्वारा सदन में रिएजेंट खरीदी की मुद्दा उठाया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में सुनियोजित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। बिना जरूरी, बिना डिमांड के रिएजेंट सप्लाई की गई। 28 करोड़ की रिएजेंट खराब हो चुकी है, और भी खराब होने की आशंका है।

बताया गया कि जिस रिएजेंट की कीमत करीब 31 हजार रुपए है, उसे करीब 1 लाख 96 हजार रुपए में खरीदा गया। डायसिस कंपनी के एक अन्य रिएजेंट की कीमत जहां 28 हजार 417 रुपए थी, वहां इसकी खरीदी 1 लाख 76 हजार रुपए में कर दी गई। इसी तरह डी डीमर एफएस रिएजेंट की खुले बाजार में कीमत करीब 70 हजार रुपए है, उसे करीब 5 लाख 86 हजार रुपए में खरीदा गया। इसी तरह अन्य दवाओं, उपकरणों और रिएजेंट की सप्लाई में बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी की गई।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट आब्जरवेशन ने बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी। ऑडिट ऑब्जरवेशन 29 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक की गई थी। इस आडिट में 193 करोड़ रुपए की खरीदी में आपत्ति जताई गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में की गई आपत्ति के बावजूद टेंडर निरस्त नहीं किया गया। मोक्षित कारपोरेशन ने अपनी सप्लाई जारी रखी।

विकसित भारत बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका महत्वपूर्ण: डेका

■ भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नही आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ रहे है तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विचार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने उदबोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते है। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर

सकते है।

श्री डेका ने कहा कि सम्मेलन का विषय भौतिक विज्ञान में उभरते रूझान इस उभरते क्षेत्र में अपने ज्ञान पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर वैज्ञानिक जांच और नवाचार के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक इस सम्मेलन में एक साथ है।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है। यह अनुसंधान नवाचार और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरक का काम करेगी। सम्मेलन युवा और नवोदित वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के माध्यम से अपने संभावित शोध को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। स्नातकोत्तर छात्रों को शामिल करना और उनकी पोस्टर प्रस्तुतियां इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ज्ञान, विचारों और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण शोध और अभिनव समाधानों के लिए यह सम्मेलन उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर स्वागत भाषण रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद ने दिया। प्रोफेसर कल्लोल घोष ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.एस धामी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर प्रसाद ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर शब्दकोश का विमोचन किया गया। राज्यपाल श्री डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एनालॉटिकल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी और नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी और उद्यमिता फाउंडेशन का उद्घाटन किया।

प्रेमी प्रेमिका निकले चाकूबाज गुंडे बुलाकर युवक को पीटा

रायपुर। चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को एक बार फिर चाकूबाजी की घटना घटी। पुलिस के मुताबिक शाम 6:30 बजे रायपुर नगर निगम के सामने वाली गार्डन में बायफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने मिलकर युवक को चाकू मार दिया। आरोप है कि प्रेमी जोड़े ने गुंडे बुलाकर उसकी पिटाई भी की। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। घायल युवक का इलाज चल रहा है।

कोतवाली थाना प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया कि गुरुवार की शाम को गार्डन में प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर एक पुराने बॉयफ्रेंड को बुलाकर चाकू मार दिया। बाद में अपने दोस्तों को बुलाकर उसकी पिटाई भी कराई। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी विक्की राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर रही है।

कोतवाली थाना प्रभारी सुधांशु बघेल ने

बताया घायल युवक के बयान के आधार पर पुलिस ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके बाद इस मामले में धारा 324 जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक लड़की के बॉयफ्रेंड ने पहले चाकू से पीड़ित युवक पर हमला किया। चाकू के हमले में युवक जख्मी हो गया। चाकूबाजी की घटना होते ही गार्डन में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गए। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है।

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर पांच अधिकारियों का सदन में हुआ निलंबन

रायपुर। दंतेवाड़ा जिले में डीएमएफ मद से सड़क निर्माण के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद डिप्टी सीएम ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी के मामले में 5 लोगों को निलंबित करने की सदन में घोषणा भी कर दी। उन्होंने इस मामले में संबंधित ठेकेदार से वसूली करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी ऐलान किया।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जिला निर्माण समिति दंतेवाड़ा के तहत डीएमएफ मद से स्वीकृत सड़कों का मामला उठाते हुए सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि क्या इस सड़क के निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इसमें किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई और जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

सवालों के बीच उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने माप पुस्तिका में दर्ज कार्यों के तहत भुगतान को लेकर सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि क्या ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है। इस पर डिप्टी

सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्य पीएम ग्राम सड़क के तहत डीएमएफ में स्वीकृत ही नहीं है। बल्कि जिला निर्माण समिति समिति के विशेष केन्द्रीय सहायता मद में स्वीकृत है।

उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस मामले में शिकायत मिली थी। दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम गठित कर प्रथम स्तरीय जांच कराई गई। इसके भौतिक सत्यापन में अर्थवर्क, जीएसबी डामरीकरण कार्य, डब्लूबीएम और सोल्डर कार्य, रिटनिंग वॉल में अनियमितता का उल्लेख है।

डिप्टी सीएम ने जांच रिपोर्ट में ठेकेदार से 2 करोड़ की वसूली का जिक्र किया। तब चंद्राकर ने पूछा कि जब भुगतान ज्यादा नहीं हुआ तो जांच समिति किस बात की वसूली कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम एक द्वारा माप पुस्तिका के आधार पर कम भुगतान और वसूली के आदेश होने की बात कही।

इस पर चंद्राकर बिफर पड़े। उन्होंने डिप्टी सीएम पर का आरोप लगाए कि आप भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं। भ्रष्टाचार को उजागर क्यों नहीं कर रहे, संरक्षण क्यों दे रहे हैं। इस बात इस पर सदन में विपक्ष ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों में तीखे लहजे में बहस और टकराव की स्थिति बन गई।

सदन में डिप्टी सीएम और भाजपा सदस्य के बीच टकराव और तौखे लहजे में बहस के दौरान आसंदी ने मामला संभाला। उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि इतनी ऊंची आवाज में न बोलें। माइक लगा है इसलिए सब धीरे बोलने से भी सुन लेते हैं। इसलिए टोन नीचे करें। आरोप-प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें।

सदन में बहस के दौरान विपक्ष के सदस्य टोकाटाकी करते रहे। डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि वो ठेकेदार जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उसका कारनामा है। क्या ठेकेदार के पूरे काम की जांच कराई जाएगी। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि निःसंदेह जांच कराई जाएगी।

इनके निलंबन की घोषणा

- डिप्टी सीएम ने सदन में दोषी अफसरों के निलंबन और कार्रवाई की घोषणा की।
- सेवानिवृत्त हो चुके कार्यपालन अभियंता अनिल राठौर के विरूद्ध जांच की जा रही है।
- कार्यपालन अभियंता दामोदर सिंह सिदार को निलंबित कर विभागीय जांच की घोषणा
- अनुविभागीय अधिकारी तारकेश्वर दीवान को निलंबित कर विभागीय जांच की घोषणा।
- सहायक अभियंता आरवी पटेल को निलंबित कर विभागीय जांच का ऐलान।
- एक उपअभियंता का निधन हो चुका है।
- उपअभियंता रविकांत सारथी को निलंबित किया जा चुका है।
- ठेकेदार के खिलाफ वसूली, जांच के आदेश हो गए हैं, एफआईआर का आदेश हो गया है।
- ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी में ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

'एक देश-एक चुनाव' बदलेगा चुनावी परिदृश्य

नीरजा चौधरी

'एक देश-एक चुनाव' की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट की मंजूरी के बाद सत्ता पक्ष ने 129 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन संख्या बल की कमी होने के कारण विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी में भेजना पड़ा। 'एक देश-एक चुनाव' भाजपा की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके पक्ष में बात की थी। वर्ष 2014 में मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद भाजपा के एजेंडे में यह मुद्दा प्रमुखता से था। पिछले साल उसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जिसने इस साल अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं। इसकी परिणति क्या होगी, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता पक्ष अगर इसे पारित कराने में सफल हो जाता है, तो इससे देश का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल जायेगा। स्पीकर ने पक्ष-विपक्ष को यह भरोसा भी दिया है कि जब यह बिल दोबारा आयेगा, तो सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जायेगा। सत्ता पक्ष ने इसे दूरगामी महत्व का बताया और विपक्ष की आशंकाओं का निराकरण करने की कोशिश करते हुए यह भी कहा कि कानून बन जाने के बाद यह राज्य को मिली शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया तो जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सरकार इसके पक्ष में दो तर्क दे रही है। एक यह कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तो बार-बार होने वाले विधानसभा चुनावों के खर्च से बचा जा सकेगा। दूसरा यह कि इससे सरकारी कामकाज बेहतर ढंग से हो सकेगा। अभी बार-बार चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण कामकाज प्रभावित होता है। शिक्षकों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। इससे मुक्ति मिलेगी। ये बातें सही हैं, पर लगता नहीं है कि एक साथ चुनाव कराये जाने से चुनावी खर्च कम हो जायेगा। इस देश में लंबे समय से जिस चुनाव सुधार की बात की जा रही है, वह दरअसल चुनावों में प्रत्याशियों और पार्टियों की तरफ से होने वाला बेतहाशा खर्च पर अंकुश लगाने से जुड़ा है। चुनावी खर्च सालोंसाल बढ़ता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं है। चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार इलेक्टोरल बांड लेकर आयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गंभीर अनियमितता पायी। लिहाजा, जिस 'एक देश-एक चुनाव' को चुनाव सुधार की दिशा में कदम बताया जा रहा है, वह सहूलियत के लिए उठाया जा रहा कदम ही ज्यादा लगता है। मेरा मानना यह है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने के बजाय पहले चरण में लोकसभा का और दूसरे चरण में सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। इससे देश की लोकतांत्रिक विविधता और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व, दोनों सलामत रहेंगे। एक साथ चुनाव कराना अगर इतना ही जरूरी है, तो इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराये गये? जब चार राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं कराये जा सकते, तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराया जाना कैसे संभव होगा? भारत जैसे विशाल देश में इतनी बड़ी कवायद को भविष्य में अंजाम देना भी बहुत कठिन होगा। 'एक देश-एक चुनाव' से देश में संघवाद की भावना कमजोर होने की भी आशंका है। संघवाद पर आघात संविधान के मूल ढांचे पर आघात से कम नहीं। विविधता भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। इस देश में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी आवाज उठाती हैं और उनके हित सुरक्षित रखने का काम करती हैं। राज्य विधानसभाओं के चुनावों में अक्सर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। मतदाता एक या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को चुनते ही इसलिए हैं कि वे उनके हितों का ख्याल रखेंगी, लेकिन चुनाव एक साथ होंगे, तो दोनों चुनावों में केंद्रीय मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी और स्थानीय मुद्दे गौण हो जायेंगे। क्षेत्रीय पार्टियां आशंकित हैं कि इससे उन सबका अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा।

क्या अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी कांग्रेस?

उमेश चतुर्वेदी

संविधान पर संसद में विशेष बहस पर अपने नेताओं प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर जिस वक्त कांग्रेस गद्गद् हो रही थी, उसी वक्त उस पर कश्मीर की वादियों से सियासी गर्मी का जबर्दस्त झोंका आया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सीधे-सीधे सलाह दे डाली कि ईवीएम का रोना छोड़ो और अपनी हार को स्वीकार कर लो। दिलचस्प यह है कि लोकसभा के अपने पहले भाषण में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि ईवीएम हटा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका के इस बयान के ठीक बाद सामने आए उमर अब्दुल्ला के ये शब्द महज बयान नहीं है, बल्कि इसके कई राजनीतिक अर्थ हैं।

उमर के इस बयान को ममता बनर्जी और रामगोपाल यादव की अभिव्यक्ति की अगली कड़ी के रूप में रखा जा सकता है। यहां एक बार फिर दोहरा देना उचित ही होगा कि इंडिया गठबंधन के अघोषित अगुआ को रूप में राहुल गांधी को नकार चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव कांग्रेस की अगुआई को ही नकार चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान के जरिए एक तरह से साफ कर दिया है कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व में उनका भरोसा नहीं है। आज की राजनीति जिस बिंदु पर पहुंच चुकी है, उसमें अगुआ की हर गलत-सही बात का समर्थन करना ही अनुयायियों की पहली शर्त बन गई है। तार्किक आधार पर समर्थन और विरोध की सोच को हमारे समाज ने सिरे से नकार दिया है। यह नकार राजनीति में सबसे ज्यादा नजर आता है। अगुआ की बात को अनुयायी ने स्वीकार नहीं किया तो उसे सीधे-सीधे नाफरमानी या अनुशासनहीनता माना जाता है। दलीय व्यवस्था में ऐसे नकार की सजा निष्कासन और निलंबन तय है। चूंकि इंडिया गठबंधन औपचारिक कोई दल नहीं, बल्कि दलों का समूह है, लिहाजा यहां वैसी अनुशासनिक व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद मोटे तौर पर गठबंधनों के बीच एक समझ रही है कि गठबंधन और उसके अगुआ की सेहत पर असर ना पड़े, ऐसी बयानबाजी से दूर रहा जाए।

लेकिन ममता बनर्जी, रामगोपाल यादव

और उमर अब्दुल्ला के बयान के संदेश साफ हैं। संदेश यह है कि कांग्रेस की अगुआई में उन्हें नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाने की ताकत राहुल गांधी में नहीं दिखती। इन बयानों का एक संदेश यह भी है कि राहुल गांधी की अगुआई में इन दलों का कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर कोई भविष्य नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला इससे आगे का भी संकेत दे रहे हैं। ईवीएम के बहाने वे कांग्रेस को यह भी संदेश दे रहे हैं कि 'मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू' की वैचारिक सोच वाली राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। यह कैसे हो सकता है कि जिस ईवीएम के सहारे आप अमेठी और वायनाड जीतने के बाद आप जश्न में डूब सकते हैं, जिसके सहारे 55 से 99 सीटों पर पहुंच जाते हैं तो इसे अपनी भारी जीत बताते हैं, जिस ईवीएम के ही सहारे जब आप कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड और यहां तक कि कश्मीर जीत जाते हैं तो इसे नरेंद्र मोदी की हार बताने लगते हैं, लेकिन अगर चुनावी रणनीति में मात खाने के बाद सत्ता की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं। यह दोहरापन नहीं चलने वाला। इसे जनता भी समझने लगी है।

अगर ईवीएम पर इतना ही संदेह है तो संदेह करने वाले दलों को चाहिए कि वे ईवीएम के जरिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करें। इसके बाद अगर चुनाव होगा तो निश्चित है कि इस चुनाव की पवित्रता सवालों के घेरे में आ जाएगी। अगर ईवीएम पर संदेह करने वाले दल चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएं तो विपक्ष विहीन चुनाव को जनता भी स्वीकार नहीं कर पाएगी और उस चुनाव को सहज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग नहीं माना जा सकेगा।

ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग दबाव में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए ईवीएम पर संदेह करने वाले दलों में साहस होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा साहस कोई दल दिखाता नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि कोई भी दल संसदीय राजनीति के उस रसूख को छोड़ने का साहस नहीं रखता, जो उसे सांसद या विधायक बनने के बाद हासिल होता है। इन दलों और उनके नेताओं को पता है कि संसद और विधानमंडल से बाहर रहने के बाद उनकी बातें गौर से सुनीं नहीं जातीं और उनके शब्दों को तवज्जो भी नहीं मिलता। इसलिए वे ईवीएम पर सवाल भी उठा रहे हैं और उसी ईवीएम के जरिए संसदीय कुर्सियों पर भी काबिज रहना चाहते हैं। यह भी एक तरह से चारित्रिक दोहरापन ही है और उमर अब्दुल्ला का यह बयान उस दोहरापन से खुद को अलग करने की कोशिश भी हो सकता है।

वैसे कांग्रेस के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो वे भी मानते हैं कि चाहे ईवीएम का मुद्दा हो या किसानों का आंदोलन, उनके लिए सिर्फ कवरअप के मुद्दे हैं। कवरअप यानी बचाव का मुद्दा। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी मानते हैं कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस राजनीति कर रही है, उन्हें उसकी ही सरकार ने तैयार किया था। ईवीएम का चलन 2004 में पूरी तरह शुरू हुआ। जिसमें कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को जीत मिली थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तब तो कांग्रेस को यह जीत बहुत पसंद आई थी। इसके अगले यानी 2009 के चुनाव में भी यूपीए को दूसरी बार जीत मिली। तब भी ईवीएम पर कम से कम कांग्रेस की ओर से सवाल नहीं उठा। तब लालकृष्ण आडवाणी खेमे की ओर से ईवीएम पर सवाल उठा तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके बाद आडवाणी के लोगों ने उसे तूल नहीं दिया। लेकिन 2014 के बाद से लगातार ईवीएम पर कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस भी जानती है कि ईवीएम में दोष नहीं है, उसकी नीतियों में ही कमी है, जिसकी वजह से वोटर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

ऑफ द रिकॉर्ड अगर कांग्रेसी नेताओं से बात होती है तो वे मानते हैं कि किसान कानून और ईवीएम का विरोध दरअसल उसके लिए बचाव के मुद्दे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए अपनी नाकामियां छिपाती रहती है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के हालिया बयान को लेकर उनके खिलाफ कपिल सिब्बल की अगुआई में महाभियोग चलाना कुछ-कुछ वैसा ही मामला होने जा रहा है, जैसा 1986 में शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद से नया कानून बना दिया गया था। बहुसंख्यक सोच जबकि इसके खिलाफ थी, कुछ इसी तरह शेखर यादव के बयान को लेकर महाभियोग चलाने के फैसले से बहुसंख्यक वोट बैंक सहमत नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लेकर बहुसंख्यक समाज में विरोध के सुर भले ही खुले तौर पर ना उठें, लेकिन चुनावी मैदान में इसे लेकर बहुसंख्यक वोट बैंक अपना गुस्सा निकाल सकता है। फिर भी कांग्रेस अपनी हार के लिए अपने रूख को लेकर सवाल नहीं उठाएगी, अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करेगी,बल्कि वह ईवीएम को ही बहाना बनाएगी।

बहरहाल उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद कांग्रेस को सबक सीखना होगा। उसे स्वीकार करना होगा कि उसकी बेतुकी बयानबाजी पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, उसके साथियों को भी एतराज है। उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि अगर उसने नीतियां नहीं बदलीं तो उसके नेतृत्व को लेकर विपक्षी गठबंधन में भरोसा कायम नहीं रह पाएगा। जिसका असर आने वाले दिनों में होने जा रहे दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के चुनाव नतीजों में दिख सकता है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

इस प्रकार आदिम चार प्रमाण स्वयं दयानन्द जी के भाष्य से उद्धत किये हैं, तथा अन्तिम प्रमाण उपनिषद् और उसके भाष्य से उतारा है। यह उपनिषदुभाष्य इटावा निवासी पं. भीमसेन जी ने उस समय रचा था जब कि आप दयानन्द शिष्य होने में अपना गौरव समझते थे। अतएव भाष्य के आवरण पृष्ठ पर ही आपने अपने नाम के साथ दयानन्दशिष्य ऐसा लिखा है।

उक्त प्रमाणों की विद्यमानता में कोई भी समाजी योग- सिद्धियों के चमत्कारों में असम्भव, नामुमकिन का अड़ङ्गा नहीं लगा सकता। सो महाभारत में भी शुकदेव जी महाराज का संदेह लोकान्तर- चारी हो जाना ही लिखा है।

यथा- शुकस्तु मारुतादूर्ध्वगति कृत्वान्तरिक्षगाम्। दर्शयित्वा प्रभावं स्वं ब्रह्मभूतोऽभवत्तदा ।। (महाभारत शान्ति0 233)

अर्थात्- शुकदेव जी वायु से ऊंची अन्तरिक्ष में चल सकने वाली गति को बना कर अपना प्रभाव दिखाते हुए ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए ।

वेद जिन योगीजनों को ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेने पर- अविद्यमा मृत्यु तीर्ध्वा विद्ययामृतमश्नुते अमृतास्ते भवन्ति आदि वाक्यों द्वारा अमर सिद्ध करता है, महाशय जी उसो योग-प्रभाव-जनित लोकान्तर- गमन-सिद्धि को मरना कह रहे हैं! यदि प्रतिवादी श्रीमद्भागवतपुराण वर्णित शुकदेव जी के आगमन को एक बार भी अपनी आँखों देख लेते तो इस प्रकार का अविवेकपूर्ण आक्षेप करने को उद्यत न होते।

जिस समय महाराजा परीक्षित प्रायोपवेशन व्रत धारण किये गङ्गातट पर बैठे थे, उस समय श्री शुकदेव जी वहाँ आये। उनका कैसा स्वरूप था यह निम्नलिखित श्लोकों में वर्णन किया गया है।

क्रमशः ...

पं. सुन्दरलाल शर्मा

सुरेंद्र कुमार

छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में विख्यात पं. सुन्दरलाल शर्मा नाट्यकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला में निपुण विद्ववान थे। उन्होने प्रदलाद चरित्र, करूणाद-पचीसी, व सतनामी-भजन-मालाा जैसे ग्रंथों की रचना की साथ ही छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा समाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते है, वे कवि, सामाजसेवक, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को छत्तीसगढ़ प्रांत में राजिम के समीप महानदी के किनारे बसे ग्राम चन्द्रपुर में हुआ था। उनके पिता का जगलाल तिवारी उस समय कांकेर रियासत में विधि सलाहकार थे, एवं उनकी माता का नाम देवमति था। पंडित सुन्दरलाल शर्मा के हृदय में बचपन से ही हिंसा के प्रति घृणा थी, वे अस्पृश्यता को भारत के गुलामी तथा समाज के पतन का कारण मानते थे। उन्होने समाज की उत्थान एवं संगठन के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा की स्कूली शिक्षा प्राथमिक स्तर तक ही हुई क्योंकि उन दिनो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था और आगे घर पर ही उन्होने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, उड़िया आदि भाषाएं भी सीख ली सुन्दर लाल शर्मा साहित्य और पढ़ाई में अत्यधिक रूचि रखते थे उनके अंदर ज्ञान और दक्षता हासिल करने की जबरदस्त ललक थी, किशोरावस्था से ही उन्होने कविताएं, लेख, एवं नाटक लिखना शुरू कर दिये थे। गांवो में अंधविश्वास, अज्ञानता सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार को अधिक महत्व देते थे।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा भाषा और साहित्य में विशेष रूचि रखने के साथ-साथ एक महान साहित्यकार थे। उन्होने हिन्दी भाषा के साथ छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा का रूप दिलाने के लिए अथक प्रयास किया, वे हिन्दी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की जिसमें छत्तीसगढ़ी दानलीला उनकी प्रसिद्ध रचना है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध-काव्य है। वे अपनी कविताओं में सुन्दर कवि उपनाम का उपयोग करते थे। उन्होने छत्तीसगढ़ी में दुलरवा पत्रिका, और हिन्दी में कृष्णा जन्म स्थान पत्रिका की रचना की।

छत्तीसगढ़ की राजनीति व देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा है, 19 शताब्दी के अंमित चरण में देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की लहरें जाग उठ रही थी, उसी समय समाज सुधारकों, चिंतको तथा देशभक्तों ने परिवर्तन के इस दौर में समाज को एक नयी सोच और सही दिशा प्रदान की छत्तीसगढ़ के गांव गांव में व्याप्त अंधविश्वास, अस्पृश्यता, समाजिक कुरीतियों, और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए समाजिक चेतना को घर-घर पहुंचाने के लिए सुन्दरलाल शर्मा ने उल्लेखनीय कार्य किया।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा ने राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, मद्यनिषेद, आदिवासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिस्कार तथा देशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया।

क्या दुनिया ट्रंप के लिए तैयार है?

शंकर अय्यर

'शक्ति कोई साधन नहीं है, यह साध्य है। शक्ति का उद्देश्य शक्ति ही है।' डोनाल्ड जे ट्रंप ने जॉर्ज ऑरवेल के अमर वाक्य को आत्मसात किया है और इसे अक्षरश: एवं भावना के स्तर पर मूर्त रूप दिया है। लगभग एक महीने बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। उनकी 1927 में बनी, 20 एकड़ में फैली 128 से अधिक कमरों वाली 'मार-ए-लागो' प्राचीन वस्तुओं से सजी हवेली, जिसके ऊपर 70 फुट ऊंचा अमेरिकी झंडा लहराता है, राजनीतिक तीर्थस्थल है।

तीर्थयात्रियों में कीर स्टार्मर, वोलोदिमीर जेलेंस्की, जेवियर माइली और जस्टिन त्रूदो शामिल हैं, जबकि मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम जैसे अन्य लोग उन्हें फोन करते हैं। उनकी वापसी पर संदेह करने वाले मेटा के मार्क जुकरबर्ग और एपल के टिम कुक जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों ने भी आकर उनका अभिवादन किया।

अमेजन के जेफ बेजोस अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वाले हैं। और सभी शपथ ग्रहण समारोह के लिए लाखों डॉलर का योगदान दे रहे हैं। उनके दर्शनार्थ आने वाले महानुभावों के मद्देनजर प्रयुक्त रूपकों में 18वीं और 19वीं शताब्दी के शाही दरबारों में देखी गई मुद्राएं शामिल हैं या फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर? फिल्म में छोटे डॉन द्वारा वफादारी दिखाने के लिए अंगूठी चूमने का सिनेमाई चित्रण।

ट्रंप खुद को न केवल कमांडर इन चीफ के रूप में देखते हैं, बल्कि मुख्य राजनयिक, मुख्य व्यापार वार्ताकार और भू-राजनीति और महत्वपूर्ण मुद्दों के मध्यस्थ के रूप में भी देखते हैं। ट्रंप के पास प्रोटोकॉल की बारीकियों के लिए समय नहीं है। उनकी घोषणाएं ट्रुथ सोशल पर स्ट्रीम करती हैं और एक्स (पूर्व ट्विटर) पर फिर से पोस्ट की जाती हैं। चीन पहले ही उनके निशाने पर है, जिसे 50 फीसदी से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। हाल में, उन्होंने अवैध प्रवासन और ड्रग्स के मुद्दे पर

मेक्सिको और कनाडा को धमकी दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि वे 'शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने की कोशिश न करें अन्यथा उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा।' ट्रंप की वापसी ने अमेरिकी बाजारों को चुनाव के बाद की शानदार ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

हालांकि, दुनिया भर में घबराहट है। वैश्विक स्तर पर रुपया सहित सभी मुद्राएं गिर रही हैं। ओसाका से लेकर मुंबई और न्यूयॉर्क तक के बाजारों में निवेशक 20 जनवरी के बाद के परिदृश्यों को समझने के लिए जूझ रहे हैं। सम्मेलनों में ट्रंप की अदृश्य मौजूदगी है और वैश्विक बैठकों, सरकारों और कंपनी सी-सूट्स में उनका नाम चर्चा में रहता है। हालांकि बाइडन प्रशासन अब भी सत्ता में है, लेकिन ट्रंप अपने नाम और काम की ताकत को पेश करने में लगे हैं। बस दो मनोनयन पर विचार कीजिए। मनोनीत विदेश मंत्री मार्को रुबियो जाने-माने कट्टर चीन विरोधी हैं और पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के लेखक हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कर संहिता को चीन में निवेश को प्रोत्साहित करने से रोकना है।

रुबियो यह भी चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकल जाएं। वाणिज्य सचिव पद के लिए चुने गए हॉवर्ड लुटनिक को सभी क्षेत्रों में उच्च टैरिफ के समर्थक के रूप में जाना जाता है। लक्ष्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। इरादा यह है कि बाहर से आने वाली सभी चीजों के मार्ग को कठिन बनाया जाए- खासतौर पर वस्तुओं और प्रवासियों को और केवल एफडीआई को अनुमति दी जाए। बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने का साधन है टैरिफ, इसके साथ ही एलन मस्क के नेतृत्व वाले प्रस्तावित सरकारी दक्षता विभाग द्वारा हल्के विनियमन और छोटी सरकार का वादा, और अमेरिका में निवेश के लिए कर छूट।

ट्रंप पहले से कहीं ज्यादा तैयार दिखते हैं। उनकी शक्ति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार और 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' के वादे से उपजी है। ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना चाहते हैं। 1970 के दशक के बाद अमेरिकी कंपनियों ने एक त्रिपक्षीय मॉडल विकसित किया, जहां उन्होंने उत्पाद डिजाइन किए, टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपने पास रखा और विनिर्माण एवं श्रम आउटसोर्स किया। नीति पर नियंत्रण से निवेश, विनिर्माण नौकरियों, आय और विकास का निर्यात हुआ। इसने समाज में एक उच्च आय का क्षेत्र बनाया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से निवेश और रोजगार खत्म कर दिया, जिससे आम जनता आय और उपभोग के दायरे से बाहर हो गई। ट्रंप को इसका एहसास है कि उन्हें भारी बहुमत मिला है और वह अपने मतदाताओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

ट्रंपोनॉमिक्स, मूलत:अतीत के गौरव को बहाल करने और मौजूदा व्यवस्थाओं को खत्म करने का वादा है। हालांकि विशेषज्ञ उच्च टैरिफ दीवार और अप्रवासियों के जबरन निर्वासन के खिलाफ तर्क दे रहे हैं कि दोनों ही मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रंप दृढ़ हैं। ट्रंप की योजना चीन से आने वाले सामान और अन्य देशों द्वारा माल के उत्पादन के लिए आयात किए जाने वाले घटकों को लक्षित करने की है। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-डॉलर के मजबूत होने से पैसे की लागत बढ़ सकती है, टैरिफ से इनपुट महंगे हो जाएंगे और अमेरिकी सामानों के लिए बाजार खोलने से स्थानीय उत्पादकों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सहयोगियों के साथ संबंधों को होने वाले संभावित नुकसान को कोई खास महत्व नहीं दिया जा रहा है। आशावादी लोग मानते हैं कि ट्रंप व्यापारी हैं और टैरिफ की धमकी बातचीत का एक साधन है। यह कुछ हद तक सच हो सकता है। लेकिन एक असमान दुनिया में- डॉलर सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है और अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है-जुड़ाव की शर्तें फिर से तय होंगी और समझौते करने होंगे।

ऐसा लगता है कि धमकियों का असर हो रहा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने यूरोपीय संघ को अमेरिकी (हथियार और तरल प्राकृतिक गैस) खरीदने और ट्रंप के व्यापार युद्ध से बचने की सलाह दी। नाटो सदस्य, जो पहले अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के दो प्रतिशत तक नहीं बढ़ाते थे, अब इसे तीन प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

आज का इतिहास

1894 मैकेंज़ी बोवेल कनाडा के पांचवे प्रधानमंत्री बनाये गए।
1898 फ्रांस के वैज्ञानिकों पियरे और मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की।
1907 चिली के सैनिकों ने सांता मारिया स्कूल में खनन कर्मचारियों को आग लगा दी।
1910 इंग्लैंड में दूसरे सबसे खराब खनन दुर्घटना में, हॉल्टन बैंक कोलियरी नंबर 3 पिट में एक भूमिगतएक्सप्लोसियन ने 344 लोगों की जान ले ली।
1913 दुनिया की पहली क्रॉस वर्ड पहेली, आर्थर वायने की वर्ड क्रास, न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशित हुई।
1919 लोगों को दो साल तक जेल में रखने के लिए जेल में भर्ती कराने के बाद, सैन्य अराजकतावादी एम्मा गोल्डमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका से रूस भेज दिया गया।
1923 नेपाल और यूनाइटेड किंगडम ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पहले से तय करता है।
1931 जेम्स स्किलिन ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
1937 रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म-डिजनीस स्नो व्हाईट का प्रदर्शन किया गया।
1962 ब्रिटेन ने अमेरिका से पोलारिस मिसाइलों की खरीदने के लिए तैयार हुआ।
1963 ग्रीक और तुर्की साइप्रस के बीच अंतर- सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हुई।
1965 संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया, जिस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 87 सदस्य हैं।
1968 केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 8 का चंद्रमा की कक्षा के लिए प्रक्षेपण किया गया।
1971 कर्ट वॉल्डहाइम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव बने।
1974 पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत आईएनएस सतवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेडे में शामिल किया गया।
1975 बफ़ेलो सबर्स ने 4-2 में 5 गोल बनाम वाशिंगटन कैप्स के स्कोर 14-2 से एनएचएल रिकॉर्ड 40 अंक बनाए।
1988 पान एमफलाइट 103 के बोर्ड में बम विस्फोट होने पर कुल 270 लोग मारे गए थे, जबकि विमान स्कॉटलैंड के लॉकेरी में उड़ान भर रहा था।

जब आंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू ने लगा दिया था जी-जान

अभिनय आकाश

13 फरवरी 2023 अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक खबर जिसका शीर्षक इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉ. आंबेडकर रेजिगनेशन लेटर लॉस्ट फ्राम द रिकार्ड यानी भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. अम्बेडकर का इस्तीफा दस्तावेजों से गायब। वो इस्तीफा जो डॉ. आंबेडकर के विचारों की दृढ़ता का सबूत था। कहानी 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात को शुरू होती है। जब आधी दुनिया सो रही थी तो हिंदुस्तान अपनी नियती से मिलन कर रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टनी वाला भाषण भारत की स्वतंत्रता का पर्याय बना। देश आजाद हो चुका था और अब बारी थी कि देश की तकदीर देश के ही लोगों के हाथों तय करने की और जिसके लिए आम चुनाव जरूरी थे। इसी क्रम में संविधान बना। जिसका अंतिम पाठ होने के बाद संविधान सभा में डा. अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। लेकिन उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह पहला विचार हैज् 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा। उस दिन से भारत की जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। क्या भारत अपने प्रजातांत्रिक संविधान को बनाए रखेगा या फिर खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना चिंताजनक है। 26 जनवरी 1950 से हम विरोधाभास से भरे जीवन में शामिल होने वाले हैं। राजनीतिक जीवन में तो समानता हमारे पास होगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में नहीं। कहने का मतलब हाशिए पर रखे गए लोगों के लिए बराबरी की बात तो तय कर दिए गए थे। लेकिन समाज और पैसे के मामले में ये अभी भी दूर की बात थी।

ऐसे ही हाशिए पर रहे एक वर्ग के लिए उन्होंने कुछ सुधार करनी की सोची। जब आजादी के बाद अंतरिम सरकार में वो कानून मंत्री बनाए गए। ये भारत की आजादी से कुछ हफ्ते पहले की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीआर अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैबिनेट के अधिकांश अन्य सदस्यों के विपरीत, अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे और न ही वे उन मूल्यों को साझा करते थे जिनमें नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। पहले कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ अम्बेडकर के संबंध अपेक्षाकृत मजबूत आधार पर टिके थे। । इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने यहां तक ??आरोप लगाया था कि नेहरू-आंबेडकर के रिश्ते को अस्पष्ट बना दिया गया है। इसके बारे में कोई किताब नहीं है, न ही मेरी जानकारी में एक अच्छा विद्वत्तापूर्ण लेख भी है। रामचंद्र गुहा की किताब मेकर्स ऑफ मार्डन इंडिया के

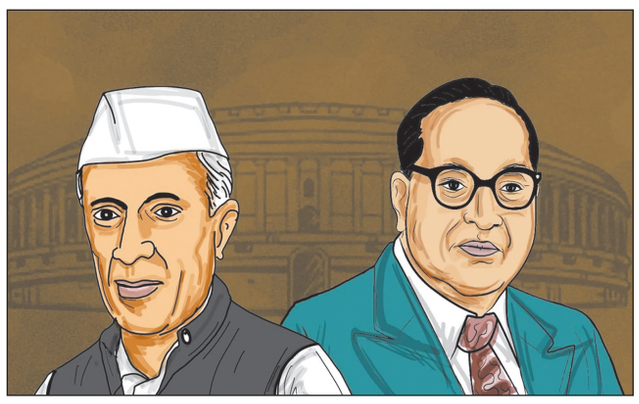

अनुसार 1940 के दशक में भारत के तब के कानून मंत्री आंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव की सोची, ताकी महिलाएं मर्जी से पति चुन सकें। तलाक ले सकें और पिता की संपत्ति में हक पा सकें। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन इसमें आगे का काम रूढिवादी नेताओं के चलते रुकने लगा।

अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मसौदा तैयार करने से पहले ही उन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसने पारंपरिक हिंदू कानून के कई वर्गों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के आदेश से संबंधित कानूनों को संबोधित करते हुए अप्रैल 1947 में संसद में विधेयक पेश किया गया था। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अम्बेडकर ने कानून को अब तक किए गए सबसे महान सामाजिक सुधार उपाय के रूप में वर्णित किया। लेकिन जबकि नेहरू का मानना ??था कि धर्म केवल निजी क्षेत्र में ही मौजूद होना चाहिए, संसद के कई सदस्य इससे असहमत थे। जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड नामक एक जर्नल लेख में, इतिहासकार रेबा सोम लिखती हैं कि नेहरू की सरकार के सदस्यों ने हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया। नेहरू ने उनके पारित होने की सुविधा के लिए संहिता को चार अलग-अलग भागों में तोड़ने का फैसला किया। हालाँकि, 1951 तक, बिल पारित नहीं हुए थे और अम्बेडकर ने निराश होकर कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया।

डॉ. आंबेडकर का राजनीतिक करियर उनके सामाजिक जीवन का ही हिस्सा था। जो कि हाशिए पर रखे लोगों के अधिकारों का जरिया था। देश को आजादी तो मिल गई थी लेकिन समाज में तमाम वर्गों के लिए काम अभी बाकी था। इस इस्तीफे के बाद उन्होंने पहले चुनाव में हाथ आजमाया। आजाद भारत के आम चुनाव दस्तक देते हैं। पांच महीनों तक चले इस चुनाव में डॉ. आंबेडकर भी मैदान में थे। साल 1952 में आंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े। लेकिन कांग्रेस ने आंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी एनएस काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर 15 हजार के करीब वोट से चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे इसलिए उसके पास, उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेहरू ने दो बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आख़िर में अंबेडकर 15 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस के नेतृत्व और नेहरू के प्रभाव का इस चुनाव पर सीधा असर रहा था। हालांकि हार के बाद आंडेबडकर ने चुनाव के नतीजों पर सवाल भी उठाए।

मूक नायक के मुताबिक ये हार उनके लिए कष्टदायक भी थी क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि बंबई के लोगों के भारी समर्थन को किस प्रकार इतनी बुरी तरह से नकार दिया गया। ये वास्तव में चुनाव आयुक्त द्वारा जांच का विषय है। आगे आंबेडकर और अशोक मेहता ने एक साझा याचिका भी दायर की और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव रद्द करने की मांग भी की। उन्होंने ये दावा किया कि 70 हजार से अधिक बैलेट पेपर रिजेक्ट कर दिए गए और गिने नहीं गए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका पर क्या कार्रवाई की ये कभी सामने नहीं आया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने बंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। वहीं अगले आम चुनाव होने तक उनका निधन हो गया।

डॉ. आंबेडकर के नाम पर संसद में हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण

शुभम कुमार

संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था कि गृह मंत्री के राज्यसभा में भाषण के दौरान संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़ी उनकी टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से भारी विवाद और हंगामा देखने को मिला, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हंगामों के चलते शीतकालीन सत्र का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है और अब इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों के पूरे दिन के लिए स्थगित होने से यही जाहिर होता है कि संसद, जो नीति निर्माण और जनता की समस्याओं के समाधान का मंच है, अब विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा बनती जा रही है। भारतीय संविधान के शिल्पकार के योगदान को किसी विचारधारा या दल विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनका जीवन और कर्म तो हर भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन संसद में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वे न केवल संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं, बल्कि ये आंबेडकर की विरासत के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करते हैं। वर्तमान दौर में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विभिन्न दलों में आंबेडकर को अपनाने और उनके नाम के इस्तेमाल की होड़ समझी जा सकती है। लेकिन उनके बुनियादी मूल्य क्या हैं, इसे लेकर चयनात्मक दृष्टि रखते हुए वोट बैंक की राजनीति करना वांछित नहीं और इस लिहाज से फिलहाल चल रही पंचायत मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश ही ज्यादा लगती है। दलितों और बहुजन की राजनीति जब केंद्र में आई, तब आंबेडकर को पर्याप्त चर्चा में लाया गया। आंबेडकर को देर से मिले भारत रत्न के आलोक में भी इसे समझा जा सकता है।?आज प्रतीकों व पहचान की लड़ाई लड़ते हुए दलितों व अल्पसंख्यकों की बात उठाने वाले राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि असुविधाजनक तथ्यों से बचते हुए सुविधाजनक सत्यों को स्वीकारने में किसी का फायदा नहीं है। आंबेडकर का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, आचरण में भी दिखना चाहिए। संसदीय कार्यवाही के बार-बार बाधित होने से महत्वपूर्ण विधेयक लंबित रह जाते हैं, नीतिगत चर्चाएं ठप हो जाती हैं और करदाताओं के धन का भी अपव्यय होता है। संसद को हंगामे का नहीं, बल्कि संवाद व सहमति का मंच होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निर्बाध ढंग से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात रखने के व्यवस्थित व रचनात्मक तरीके अपनाने चाहिए। बातें व मुद्राएं बनाने से कुछ नहीं होगा। राजनेता सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इससे जनता का कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता होना तो यह चाहिए कि पक्ष व विपक्ष मिलकर जनता के कल्याण के रास्ते तलाशें।

'गरीब की जोरू' वाली स्थिति में है कांग्रेस

अरविंद मोहन

अगर उमर अब्दुल्ला के बयान का मतलब नैशनल कांफ्रैंस का आधिकारिक बयान है तो अभिषेक बनर्जी के बयान को भी तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानना चाहिए। और हम-आप मानें न मानें लेकिन जब ई.वी.एम. के दुरुपयोग के सवाल पर उमर अब्दुल्ला के बाद अभिषेक बनर्जी भी मिलता-जुलता बयान दे रहे हैं तो कम से कम कांग्रेस को तत्काल इसका नोटिस लेना चाहिए। यह सवाल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के नतीजों के बाद वोटिंग मशीन के दुरुपयोग पर उठाए जाने वाले हंगामे के बाद ही विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर एक दौर में सभी गैर-कांग्रेसी सांझीदारों द्वारा ममता बनर्जी को नेता बनाने की मांग के साथ सामने आया है। इसमें कांग्रेस या सपा-राजद जैसे विपक्षी दलों द्वारा चुनाव हारने के बाद (और उसी मशीन से चुनाव जीतने के बाद चुप्पी साध लेने) वोटिंग मशीन पर सवाल उठाने का सवाल भी है लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की मंशा भी शामिल है।

जब से मौजूदा सरकार ने चुनाव आयुक्तों के चुनाव के पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय गृहमंत्री को सदस्य और चयन समिति में सरकार के साफ बहुमत की व्यवस्था की है तब से कांग्रेस ही नहीं लगभग पूरा विपक्ष आयोग के फैसलों और चुनाव के नतीजों को लेकर शंका जाहिर करता रहा है लेकिन उसने कभी भी इसे आर-पार की लड़ाई का सवाल नहीं बनाया है। इसलिए उसकी मांगों का वजन हल्का होता गया है। पर कांग्रेस नेतृत्व पर इस सवाल को उठाने के साथ 'इंडिया' गठबंधन के कामकाज को व्यवस्थित करने और नेता चुनने का दबाव अभी ज्यादा लग रहा है। और वह भी स्वाभाविक है क्योंकि चुनावों के चक्कर में वह इस विपक्षी गठबंधन के कामकाज को व्यवस्थित करना भूल गई थी। एक तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 'इंडिया' के संयोजक हैं और उन्होंने लंबे समय से कोई बैठक नहीं बुलाई है। दूसरे इस विपक्षी गठबंधन के बीच खटर-पटर की खबरें भी आती रही हैं और अब तो यह पक्का लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 'आप' और कांग्रेस अलग-अलग ही लड़ेंगे। कहां तो अब तक एक सांझा नीति वक्तव्य और कार्यक्रम तय हो जाना चाहिए था और कहां अभी हर चीज बिखरी ही दिखती है।

बल्कि जो चीजें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद व्यवस्थित लग रही थीं उनमें भी गड़बड़ नजर आने लगी है। कांग्रेस और सपा के, कांग्रेस और राजद के, कांग्रेस और नैशनल कांफ्रैंस के तथा कांग्रेस और द्रमुक के रिश्तों में निश्चित रूप से गिरावट आई है। 'आप' की चर्चा पहले की ही जा चुकी है और अब बगावती ममता बनर्जी के तेवर और कठोर हुए हैं। इन सबका रिश्ता हरियाणा और महाराष्ट्र ही नहीं जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से है और आगे दिल्ली या बिहार विधान सभा चुनाव में भी उसके कोई बहुत अच्छा करने की उम्मीद नहीं है। पर कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन 'इंडिया' गठबंधन के नेतृत्व के मामले में हुआ है। कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने खास सवालों पर ज्यादा उदारता दिखाई है लेकिन व्यवस्थित फैसले कराने में उनकी भी रुचि नहीं लगती। जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने सबकी इच्छा के अनुसार चुटकी बजाते खड़ा कर दिया था वह खुद नीतीश को साथ न रख पाया और आज यह हालत है कि खुद कांग्रेस 'गरीब की जोरू' वाली स्थिति में है जिसे हर कोई उपदेश पिला रहा है। कभी कोई शिव सैनिक कांग्रेस से खानदानी दुश्मनी की याद दिलाता है तो कभी अबू आजमी भी चार फटकार लगा देते हैं।

ममता तो बहुत बड़ी हैं पर 'इंडिया' गठबंधन के नए नेता लोग भी कांग्रेस को सीख देने में पीछे नहीं रहते। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद साथी लालू यादव भी ममता को नेता बनाने की वकालत कर चुके हैं। बल्कि इस सवाल पर अकेले तेजस्वी यादव ने संतुलित बयान दिया कि ममता को नेता मानने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन फैसला तो सबकी सहमति से ही होगा। कांग्रेस पर भाजपा की तरफ से लगातार हमले जारी हैं तो इसलिए नहीं कि लोक सभा के अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कुछ कमजोर पड़ी है और जीत से भाजपा की हताशा खत्म हुई है।

भाजपा की रणनीति 'इंडिया' गठबंधन के सांझीदारों की तरह कांग्रेस पर ज्यादा दबाव बनाकर कुछ सौदेबाजी कर लेने की भी नहीं है। उसे कांग्रेस और राहुल के रूप में ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। क्षेत्रीय पार्टियां भले ही उसे चुनाव में ज्यादा गंभीर चुनौती दें लेकिन पूरी राजनीति में आज उसे सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी या गांधी-नेहरू परिवार से ही चुनौती मिलती है। इसलिए वह तो अपना हमला तेज करेगी ही और मात्र संयोग नहीं है कि मीडिया और अनेक संस्थाओं से उसे समर्थन मिलता है जबकि कांग्रेस इन सबको भी दुश्मन बनाए हुए है। कांग्रेस भी किन मुद्दों को सामने करके भाजपा को बैकफुट पर धकेले यह उसकी आंतरिक चर्चा और बाहर की चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हर तरफ से कांग्रेस और खास तौर से राहुल को उपदेश पिलाया जा रहा है।

इस सबमें हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ बड़े सवाल ये हैं कि राहुल और कांग्रेस कुछ सीखते क्यों नहीं। वह पार्टी संगठन और 'इंडिया' गठबंधन के संगठनात्मक स्वरूप पर ध्यान क्यों नहीं देते। उनके बोलने का विषय कौन तय करता है, उनके राजनीतिक कार्यक्रम कौन बनाता है। वह क्यों बार-बार संघ परिवार द्वारा बिछाए सावरकर वाले जाल में फंसते हैं जबकि यह सब सैटल मैटर है। और सबसे बढ़कर यह है कि राहुल छोटी-छोटी सफलताओं से इतना इतराते क्यों हैं (हालांकि बड़ी से बड़ी पराजय की परवाह न करके आगे बढना उनका गुण है। संसद में एक अच्छा भाषण देकर अपने दोस्तों को आंख मारना या अमरीका यात्रा में भारत में एजैंडा सैटिंग का दावा करना ऐसे ही मामले हैं।

कृतघ्नता का प्रतीक है बंगलादेश

मोहन लाल

पहले पाठक कृतघ्न शब्द को समझें तो मैं लेख को आगे बढ़ाऊं। एक औरत थाली में कुत्ते का पका हुआ मांस ले जा रही थी। किसी ने उस औरत से पूछा कि तुम यह थाली में सजा कर क्या ले जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं कुत्ते का पका हुआ मांस खाने के लिए ले जा रही हूं कि रास्ते में इसे किसी कृतघ्न की नजर न लग जाए। तो पाठको, आप समझ गए होंगे कि कृतघ्न कौन होता है। मांस ले जा रही औरत से भी नीच, कुत्ते के पके हुए मांस से भी नीच, कृतघ्न अधम से भी अधम है। उसकी नजर कुत्ते के पके हुए मांस पर भी पड़ जाए तो वह खाने के लायक नहीं रहता। तो आप समझ गए होंगे कि कृतघ्न कितना घातक होता है। कृतघ्न वह है जो किसी के किए उपकार को न माने। यानी निंदक। ऐसे नीच, निंदक, व्यक्ति को कोई मुंह नहीं लगाता। निंदक को दूर से सलाम करें और निकल जाएं। यह हाल कृतघ्न देश 'बंगला देश' का है।

जिस बंगला देश को भारत ने बनाया, वह आज भारत को आंखें दिखा रहा है। 'बंग बंधु' जिन्हें 'बंगलादेश' का संस्थापक कहा जाता है। उसकी बेटी के अधोवस्त्र सरेआम लहरा रहा है। उसकी बेटी को देशद्रोही ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तरह-तरह के मुकद्दमे चला रहा है जिस भारत ने 1971 में पाकिस्तान और बंगलादेश के लाखों लोगों को जंग के दिनों पनाह दी, वही कृतघ्न 'बंगला देश' भारत को आज आंखें दिखा रहा है। हिंदू समुदाय पर हमले कर रहा है। हिंदुओं की बहू-बेटियों की आबरू लूट रहा है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा है। इस्कान जैसे धार्मिक प्रतिष्ठान के मुखिया को गिरफ्तार कर रहा है। जिस भारत ने चार लाख बंगलादेशी महिलाओं के बलात्कार की बात उजागर की उसे घृणित दृष्टि से देख रहा है। जिस भारत ने पाकिस्तानी फौजी छावनियों से 593 बंगलादेशी महिलाओं को सैक्स वर्कर के रूप में कैद महिलाओं को मुक्त करवाया उसी हिंदुस्तान को पंगु देश कह रहा है।

जिस पाकिस्तान ने 1971 तक बंगलादेश वासियों पर जुल्म ढहाए, वही 'बंगलादेश' पाकिस्तान के साथ संधि समझौते कर रहा है? कार्यकारी राष्ट्रवादी यूनिस साहिब भारत को गाली दे रहे हैं। अल्प संख्यक 'बंगलादेश' वासियों की संपत्ति को लूटते देख मुस्कुरा रहा है ऐसे

कृतघ्न पड़ोसी देश के राष्ट्रपति से मुझे स्वयं घृणा हो रही है? ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति होने का अधिकार किस ने दिया? वह भी धिक्कार के हकदार हैं। जो राष्ट्रपति होते हुए अपने देश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को बहाल नहीं रख सकता, वह राष्ट्रपति कैसा। 1947 में पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी परन्तु पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। उन्हें राजनीतिक चेतना पर गर्व था परन्तु पाकिस्तान ने सत्ता में बंगलावासियों को कभी अपने बराबर नहीं होने दिया। राजनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान ने बंगलादेश वासियों को कभी भी उनका बनता हक नहीं दिया।

1970 में पाकिस्तान 'बंगला देश' सहित आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में शेख मुजीब-उर-रहमान की 'अवामी लीग' पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। याहिया खान ने जनरल टिक्का खान की ड्यूटी लगाई कि 'बंगला देश' के हालात ठीक करो परन्तु जनरल टिक्का खान ने 'बंगला देश' वासियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। यह बात अलग थी कि आम चुनावों में शेख मुजीब-उर-रहमान को पाकिस्तान संसद में बहुमत प्राप्त हुआ था। परन्तु पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के स्थान पर जेल में डाल दिया। बस यहीं से 'बंगला देश' की नींव पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त नरसंहार किया। इससे 'बंगला देश' में भारी विरोध हुआ।

पाकिस्तानी फौज ने निरपराध, हथियार-विहीन जनता पर अत्याचार जारी रखा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि इस नरसंहार को रोका जाए. परन्तु किसी भी देश ने भारत के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक हालात में 'दुर्गा' बन कर सामने आईं। उन्होंने 'बंगला देश' को आजाद करवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ यह युद्ध 16 दिसम्बर, 1971 तक चला। इस युद्ध में भारतीय सेना के कमांडेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे पाकिस्तानी फौज के जनरल ए.के. नियाजी ने सेना सहित आत्मसमर्पण कर दिया। 25 मार्च 1971 को शुरू हुए 'आप्रेशन सर्च लाइट' के अधीन खूब हिंसा हुई। इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। चार लाख 'बंगला देश' महिलाओं की आबरू लूटी गई।

इस सारे युद्ध में शेख मुजीब-उर-रहमान 'हीरो' बन जेल से बाहर आए। उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया। याद रहे 93,000 पाकिस्तानी फौजियों का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना दुनिया के इतिहास में एक फौजी दुर्घटना थी। शेख मजीब-उर-रहमान 'बंग बंधु' की उपाधि से नवाजे गए परन्तु इसे 'बंगला देश' का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उसी बंग बंधु की 1975 को उन्हीं के पार्टी के कुछ गद्दारों और जूनियर रैंक के फौजी सैनिकों ने हत्या कर दी। उनके सारे परिवार को मार दिया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त मुजीब-उर-रहमान की दोनों पुत्रियां शेख हसीना और शेख रेहाना पश्चिम जर्मनी की यात्रा पर थीं। वह बच गईं। शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री भारत सरकार से सहयोग करती थीं। वह कृतघ्न नहीं थीं। यद्यपि 'बंगला देश' इस्लामिक देश था परन्तु शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री धर्म निरपेक्षता का पक्ष लेती रहीं। एक मित्र-पड़ोसी देश 'बंगला देश' बना रहा परन्तु पता नहीं उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। लोगों का रोष सड़कों पर उतर आया। 'बंगला देश' न जाने क्यों भारत से किस बात का बदला लेना चाहता है। शायद 'बंगला देश' की भारत द्वारा दिखाई गई कृतघ्नता का परिणाम है।

सांसद प्रियंका से कांग्रेस खुश, भाजपा असहज?

हरीश गुप्ता

प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में अपनी पहली उपस्थिति के लिए भले ही केरल के सुदूर दक्षिण स्थित वायनाड को सुरक्षित ठिकाना चुना हो, लेकिन पिछले सप्ताह लोकसभा में उनकी मुस्कुराहट भरी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ, शुद्ध हिंदी में दिए गए पहले भाषण से संसद में बिताए गए अच्छे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। उन्होंने अगर मजाक उड़ाया, तो मर्मस्थलों पर भी प्रहार किया। हालांकि उन्होंने ज्यादातर लिखित नोट्स और टेक्स्ट से बात की, लेकिन वे सहज थीं, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता था कि कांग्रेस की तरफ से वे मजबूती से भाजपा का मुकाबला कर सकती हैं। भले ही वे चौथी पंक्ति में बैठी थीं। नेहरू-गांधी परिवार की ये नवीनतम सदस्य भाजपा के रणनीतिकारों को आने वाले दिनों में उनका मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। प्रियंका ने अपना संयम बनाए रखा और कभी विचलित नहीं हुईं या अपना आपा नहीं खोया। अपने 32 मिनट के भाषण में, जिसमें तीखे कटाक्ष और आलोचनाएं कीं, उन्होंने न केवल भाजपा पर निशाना साधा, बल्कि मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ''पहले राजा भेष बदल कर आलोचना सुनने जाते थे। आज पीएम भेष तो बदल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है।'' गांधी भाई-बहन के बीच तुलना अपरिहार्य है, क्योंकि भाजपा सांसदों ने स्वीकार किया है कि प्रियंका की हिंदी में धाराप्रवाहता और राजनीतिक कौशल उनके भाई से बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने अलग-अलग दिनों में एक ही विषय पर बात की और वे अलग दिखीं। कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं क्योंकि वह विनम्र, अच्छी श्रोता और प्रेरक हैं। वह अपने भाई के करियर के लिए भले ही खतरा न बनें लेकिन वह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, वैसा ही प्रदर्शन अगर जारी रखती हैं तो पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक प्रोन्नति की मांग बढ़ेगी। यह स्पष्ट हो गया है कि जब संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था, तब भाजपा को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला था। हालांकि उस समय दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन एनडीए दलों ने व्हिप जारी किया था और यह शक्ति परीक्षण का पहला मौका था। स्पष्ट रूप से, अगर मोदी सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसे बहुत अधिक जमीनी तैयारी करनी होगी। इस मुद्दे को जेपीसी को भेजा गया है और सरकार को आने वाले महीनों में विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। सरकार ने दावा किया कि रामनाथ कोविंद पैनल के समक्ष 32 राजनीतिक दलों ने 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन किया था। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भाजपा के पास अपने 303 लोकसभा सांसदों और सहयोगियों के साथ 363 सांसदों का विशाल जनादेश था, तब ये दल उनके साथ थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति बदल गई क्योंकि भाजपा स्पष्ट बहुमत पाने में विफल रही और सहयोगियों के साथ उसकी सीटें 300 से कम रहीं। आने वाले महीनों में पार्टी कुछ और विधानसभाओं में जीत सकती है, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, यहां तक कि उसके सहयोगी भी, इस स्थिति से खुश नहीं हैं। इसलिए, कई समझदार लोगों ने एक 'मध्य मार्ग' सुझाया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि मई 2029 में निर्धारित समय पर लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और भारत भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव ढाई साल बाद कराए जा सकते हैं। राज्यों के चुनाव क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखेंगे और साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति मतदाताओं के मूड को भी दर्शाएंगे।

हैप्पी वाइब्स के लिए घर में जरूर रखें ये चीजें

घर में हैप्पी वाइब्स के लिए आपको कई छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे, घर में पौधे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आइए, जानते हैं कौन-सी हैं वे चीजें

जिंदगी में गुड वाइब्स का बहुत ही महत्व होता है। खुश रहने और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ऐसे में घर में हैप्पी वाइब्स के लिए आपको कई छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे, घर में पौधे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है इसलिए अगर आप घर में इनडोर प्लांट लगाते हैं, तो यह घर के माहौल और मूड के लिए कुछ चीजों को घर में जरूर रखें।

कलरफुल पेंटिंग

घर में कलरफुल पेंटिंग रखना न भूलें। इससे भी घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। जानवरों और पक्षियों की पेंटिंग रखने से मन शांत रहता है। वहीं, आप श्री गणेश और कृष्ण जी और राधा रानी की पेटिंग भी घर में लगा सकते हैं। ये काफी शुभ मानी जाती है।

विंड चाइम

विंड चाइम की आवाज को काफी पॉजिटिव माना जाता है। कहते हैं इसकी मीठा आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है इसलिए आपको विंड चाइम भी ड्राइंग रूम में जरूर लगाना चाहिए।

स्टार लाइट्स

रात के वक्त आपको अपना घर और भी खूबसूरत नजर आएगा, अगर आप घर में स्टार या राइज लाइट्स लगाएंगे। गुड लक और हैप्पी वाइब्स के लिए लाइट्स को भी घर में जरूर लगाएं।

एसेंसियल ऑयल्स

ऑयल्स भी आपके दिमाग को शांत रखने के लिए कारगर हैं। शाम के समय डिफ्यूजर में आप लैवेंडर, रोज या फिर रोज मेरी ऑयल्स डाल सकते हैं। इससे पूरे घर में महक रहती है और मन भी काफी खुश रहता है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल खरीद सकते हैं।

लहंगे में क्लासी और ग्लैमरस लुक पाने के लिए बेस्ट हैं ये न्यू डिजाइंस चोकर सेट, आप भी करें ट्राई

अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो आप चोकर स्टाइल सेट वियर कर सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ न्यू डिजाइंस वाले चोकर सेट दिखाने जा रहे हैं।

महिलाओं और लड़कियों को लहंगा कैरी करना बहुत पसंद है। वहीं महिलाएं लहंगे में अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ज्वेलरी कैरी करती हैं। लेकिन स्टाइलिश लुक पाने के लिए जरूरी है कि आप सही ज्वेलरी का चुनाव करें। हालांकि ज्वेलरी में आपको कई सारे पैटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो आप चोकर स्टाइल सेट वियर कर सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ न्यू डिजाइंस वाले चोकर सेट दिखाने जा रहे हैं। आप लहंगे के साथ खूबसूरत, ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक पाने के लिए न्यू डिजाइंस वाले चोकर सेट वियर कर सकती हैं।

स्टोन वर्क चोकर सेट

आप लहंगे के साथ स्टोन वर्क चोकर वियर कर सकती हैं। यह न्यू लुक पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के चोकर सेट में स्टोन वर्क किया हुआ है। साथ ही इस सेट में मोती लगे हुए हैं। आप मार्केट में 400 रुपए तक इस तरह का चोकर सेट खरीद सकती हैं।

पर्ल वर्क चोकर

अगर आप हैवी वर्क और लाइट कलर का लहंगा वियर कर रही हैं, तो आपको पर्ल वर्क चोकर सेट पहनना चाहिए। यह आपको स्टाइलिश और खूबसूरत लुक देने का काम करेगा। इस चोकर सेट में स्टोन और मोती है। यह आपके लुक को रॉयल बनाएगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइल दोनों जगह से 500 रुपए में इस तरह का चोकर सेट ले सकती हैं।

कुंदन वर्क चोकर

अगर आप डार्क कलर का लहंगा पहन रही हैं, तो आप कुंदन वर्क वाला चोकर सेट वियर कर सकती हैं। यह न्यू लुक पाने के लिए बेस्ट है। इस सेट में मोती वर्क है और यह आपके लुक को स्टाइलिश बनाएगा। आप मार्केट में 600 रुपए तक की कीमत में इस तरह का चोकर सेट ले सकती हैं।

सिंपल चोकर सेट

अगर आप सिंपल लुक पाना चाहती हैं, तो आप सिंपल चोकर सेट पहन सकती हैं। यह आपको न्यू लुक देने के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।

सर्दियों में स्टाइलिश दिखने के लिए खरीद रही हैं बूट्स?

मौसम में स्टाइलिंग का तरीका बदल जाता है। सर्दियों के मौसम ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ ही बूट्स पहनना पसंद करते हैं। यहां जानिए बूट्स खरीदने के टिप्स-

सर्दियों का मौसम स्टाइलिंग काफी चेंज हो जाती हैं। इस मौसम के लिए लोग अपने कपड़ों के साथ ही फुटवियर में भी बदलाव करते हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग बूट्स पहनना पसंद करते हैं। कुछ आप इस सीजन में बूट्स पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन्हें खरीदने से पहले कुछ टिप्स को ध्यान में रखना होगा। अगर फुटवियर कम्फर्टेबल न हो तो इन्हें पूरे दिन पहनना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए बूट्स खरीदने के टिप्स

बूट्स की लेंथ पर दें ध्यान

बूट्स कई वैरायटी में आते हैं। इसमें एंकल लेंथ बूट्स, नी-हाई बूट्स, थाई हाई बूट्स आते हैं। अब आपको अपने मुताबिक इसकी लेंथ को चुनना होगा। एंकल लेंथ बूट्स कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, इस लेंथ के शूज पहनने से ज्यादातर लोगों को शू-बाइट होने की शिकायत होती है। इसलिए खरीदने से पहले इसे पहनें और लेंथ देखें।

पैटर्न पर दें ध्यान

बूट्स में कई तरह के पैटर्न होते हैं। जैसे किसी में साइड चेन होती है तो किसी में बैक चेन होती है। ऐसे में आप अपने मुताबिक पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत और कंफर्ट को देख कर बूट्स के पैटर्न को चुनें।

चमड़ा या कपड़ा

चमड़े के बने बूट्स थोड़े सख्त, टिकाऊ होते है। इसी के साथ ये बूट्स पसीने की नमी को जूते से बाहर निकलने देता है। इसी के साथ कपड़ों के बूट्स आरामदायक होते हैं। फैब्रिक फुटवियर चमड़े के जूतों की तरह सख्त या टिकाऊ नहीं होंगे, लेकिन आरामदायक होंगे जो पैरों में सांस लेने की क्षमता बढ़ाते हैं।

आरामदायर होना है जरूरी

बूट्स खरीदते समय ध्यान रखें की वह आरामदायक हों। जरूरी नहीं की महंगे की ओर जाएं। आपको अपने कमफर्ट लेवल को चेक करना होगा।

लूज कपड़ों की इंस्टेंट फिटिंग करने के लिए काम आएंगे ये स्टाइलिंग हैक्स

कभी-कभी कोई ड्रेस खरीदते हुए कारण यह भी होता है कि ड्रेस इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि आप इसके साइज पर ध्यान ही नहीं देते और इसका साइज बड़ा निकल आता है। आइए, जानते हैं ट्रिक्स

कभी-कभी ऐसा होता है कि लोकल मार्केट या ऑनलाइन वेबसाइट पर हमें कोई ड्रेस पसंद आ जाती है और हम उसे खरीद लेते हैं। हमें वह ड्रेस इतनी पसंद आती है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि उस ड्रेस का साइज काफी बड़ा है। हमें लगता है कि हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसके अलावा एक कारण यह भी होता है कि ड्रेस इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि आप इसके साइज पर ध्यान ही नहीं देते और जब आप कहीं जाने के लिए इस ड्रेस को पहनते हैं, तो ड्रेस की फिटिंग सही नहीं आती। ऐसे में आप ड्रेस को निकालने से अच्छा इसे टेम्परेरी फिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए कई कवरअप हैक्स भी आपके काम आएंगे।

सेफ्टी पिन से फिट करें

आपके खरीदे हुए कपड़े की फिटिंग में अगर मामूली-सा अंतर है, तो आप इसे सेफ्टी पिन से भी फिट कर सकते हैं। खासतौर पर कंधों पर अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन लगा लें। वहीं, अगर स्लीव्स लंबी हैं, तो आप इसे मोड़ भी सकते हैं।

बेल्ट लगाएं

आपकी ड्रेस अगर कमर से ज्यादा लूज हो रही है, तो आप इसके लिए बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट काफी स्टाइलिश भी लगती है और इससे आपकी लूज ड्रेस फिट भी नजर आएगी।

जैकेट कैरी करें

किसी ड्रेस के ऊपर डेनिम या फ्लोरल प्रिंट जैकेट भी बहुत अच्छी लगती हैं। इससे आपकी ड्रेस ज्यादा हाइलाइट भी नहीं होगी और आपका नया स्टाइल भी क्रिएट हो जाएगा। आप ड्रेस कलर के हिसाब से ही जैकेट कैरी करें, वरना डेनिम जैकेट लगभग हर ड्रेस के साथ मैच हो जाती है।

हर फंक्शन के लिए ट्राई कर सकती हैं ये शरारा सूट

आप इस वेडिंग सीजन शरारा सूट ट्राई कर सकती हैं। शरारा सूट के हैवी डिजाइन भी मार्केट में हैं जो आपको एलिगेंट लुक भी देंगे और हर कोई आपको कॉम्प्लिमेंट करेगा। इसमें हैवी ज़री इम्ब्रायडरी, मिरर वर्क, थ्रेड इम्ब्रायडरी और लेस से सजे हुए खूबसूरत डिजाइंस मिल जायेंगे आप अपनी मनपसंद का डिजाइन सेलेक्ट कर सकती हैं।

शरारा सूट ट्रेडिशनल होने के साथ ही ग्लैमरस लुक भी देता है। महिलाएं शरारा के नए-नए डिजाइंस ट्राई करती है क्योंकि इसे कैरी करना बहुत आसान है आप चाहें तो इसे किसी भी फंक्शन में पूरे दिन में पहन सकती हैं यह आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने देगा। शरारा सूट पहनने के बाद बेहद खूबसूरत भी लगता है। आप सर्दियों में किसी फंक्शन के लिए हैवी शरारा डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप गर्मियों में शरारा पहनना चाहती हैं तो सिंपल कुर्ती के साथ शरारा के ट्रेंडी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। आजकल मार्केट में कई तरह की वैराइटी के शरारा सूट उपलब्ध हैं। आप शरारा के स्टाइलिश डिजाइन को कई तरह से कैरी कर सकती हैं।

वन लेयर शरारा

वन लेयर शरारा सिम्पल होता है। अगर आप प्लेन शरारा ट्राई कर रही हैं तो इसके साथ आप प्रिंटेड कुर्ती ट्राई कर सकती हैं। वन लेयर शरारा सिम्पल ही खूबसूरत लगता है लेकिन आप चाहें तो इसे लेस या धागे की एम्ब्रायडरी से सजा सकती हैं यह देखने में खूबसूरत लगेगा।

चिकनकारी शरारा

चिकनकारी का शरारा गर्मियों में बहुत कूल लगता है इसके साथ सिम्पल कुर्ती अच्छी लगती है। चिकनकारी का शरारा देखने में काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है। इसको आप किसी दिन के फंक्शन के लिए भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी। आप इसको किसी लेस वाली कुर्ती के साथ भी ट्राई कर सकती हैं।

नेट शरारा डिजाइन

आप किसी खास फंक्शन के लिए शरारा ट्राई करना चाहती है लेकिन आपको ज्यादा चमक दमक या एकदम सिम्पल डिजाइन का शरारा नहीं चाहिए तो आप ब्लैक नेट का शरारा ट्राई कर सकती हैं। इसे आप कंट्रास्ट कलर की कुर्ती के साथ कैरी कर सकती हैं। ब्लैक कलर आपको स्टाइलिश लुक देगा और ज्यादा भड़कीला भी नहीं दिखेगा। इसके साथ हैवी ट्रेंडी दुपट्टा कूल लगेगा।

थ्री लेयर शरारा

यह देखने में सिम्पल भी होता है और ट्रेंडी भी लगता है। थ्री लेयर शरारा सिम्पल फेब्रिक में ही अच्छा लगता है। इसे शार्ट कुर्ती के साथ कैरी करें। इसे आप लेस से सजा सकते हैं। इसके साथ थोड़ी हैवी शार्ट कुर्ती कैरी की जा सकती है। इसकी आपको कई वैरायटी मिल जाएगी आप अपनी पसंद से डिजाइन करा सकती हैं। इसके साथ अपनी मनपसंद जूलरी कैरी करें यह आपको स्टाइलिश लुक देगा।

बालों को देना है नया लुक तो यह प्रक्रिया अपनाएं

आजकल हेयर एक्सटेंशन का चलन बढ़ गया है यह बहुत समय तक खराब नहीं होता है इसमें एक्टेंशन आपके बालों से बांड्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसकी सहायता से आप अपने बालों को अपनी मन मुताबिक लम्बाई दे सकती हैं। इसमें एक्सटेंशन को बालों में इस तरीके से अटैच किया जाता है जिससे यह आसानी से आपके बालों नैचुरल रूप से लम्बा दिखाता है।

आजकल हेयर एक्सटेंशन का चलन बढ़ गया है यह बहुत समय तक खराब नहीं होता है इसमें एक्टेंशन आपके बालों से बांड्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसकी सहायता से आप अपने बालों को अपनी मन मुताबिक लम्बाई दे सकती हैं। इसमें एक्टेंशन को बालों में इस तरीके से अटैच किया जाता है जिससे यह आसानी से आपके बालों नैचुरल रूप से लम्बा दिखाता है। हेयर एक्सटेंशन दो तरह के होते हैं सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक एक्सटेंशन क्लिप की सहायता से अटैच किये जाते है। इनमें आपको बहुत से शेड मिल जायेंगे। इनमें ब्राउन, पिंक, रेड,ब्लू, येलो, जैसे शेड्स मिलते हैं। नैचुरल हेयर एक्सटेंशन में असली बालों को प्रोसेस्ड करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है।

शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन

अगर आप किसी खास फंक्शन के लिए बालों को अलग लुक देना चाहती हैं तो शार्ट टर्म एक्सटेंसन आपके लिए ही है। इसमें हेयर क्लिपों को आपके बालों से चिपका दिया जाता है। यह एक दिन के लिए ठीक रहता है। इसको आप आसानी से निकाल सकती है। लेकिन हेयर एक्सटेंशन हफ्ते के लिए चाहती है तो टेम्परेरी ग्लू ऑन बॉण्डेड एक्सटेंशन करा सकती हैं। इस विधि से बालों के स्कैल्प पर लिक्विड ग्लू लगाकर एक्सटेंशन को लगाया जाता है। अगर आप इनको निकालना चाहती है तो हेयर स्टाइलिस्ट की मदद ले सकती है। हेयर स्टाइलिस्ट ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट की सहायता से हेयर एक्सटेंशन को निकाल देंगे।

लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन

इस एक्सटेंशन में काफी समय लगता है और यह छह से आठ महीनों तक आराम से चल जाते है। इसमें एक्स्टेंशन बालों के ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। इसमें पहले बालों को सीधा किया जाता है फिर केराटिन की सहायता से एक्सटेंशन को बालों से चिपका दिया जाता है। इस तरीके से बालों को बहुत नुकसान

पहुंचता है क्योकि इसमें गर्म रॉड की सहायता से एक्सटेंशन को बालों से चिपकाया जाता है। अगर आप ठीक से ख्याल रखेंगी तो यह साल भर से ज्यादा टिके रह सकते हैं। अगर आपको इससे किसी तरह की स्किन एलर्जी है तो पहले ही अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बता दें। लॉन्ग टर्म एक्स्टेंसन को आप कलर भी कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सटेंसन में नैचुरल बालों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यह देखने में ज्यादा नेचुरल लगते हैं। यह प्राइज में थोड़े ज्यादा होते हैं।

हेयर एक्सटेंशन में कैसे करें बालों की देखभाल

हेयर एक्सटेंशन के बाद अपने बालों का खास ख्याल रखें क्योकि अगर आपको हेयरफाल या किसी तरह की स्कैल्प में एलर्जी की समस्या हो गई तो हेयर एक्सटेंसन समय से पहले निकल सकता है। अगर आपने शार्ट टर्म एक्सटेंसन कराया है तो उसको हफ्ते भर में बदल दें नहीं तो एलर्जी की परेशानी हो सकती है। बालों के लिए सॉफ्ट शैम्पू का इस्तेमाल करें। बालों के लिए मॉश्चराइजर बेस्ड शैम्पू का यूज़ अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि बालों को ज्यादा मोड़ना नहीं है बालों को सीधा रख कर ही शैम्पू करें। बालों को बहुत देर तक गीला ना रखें।आपने ग्लू ऑन बॉण्डेड एक्टेंशन कराया है तो बालों में तेल लगाने से बचें। अगर आपने लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन लगवाया है तो उन्हें भी चार या पांच हफ्तों में एक बार निकाल दें। हेयर एक्सटेंसन की क्वालिटी जरूर चेक कर लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जेपीसी को भेजे गए एक देश-एक चुनाव से जुड़े विधेयक

नई दिल्ली। लोकसभा ने देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित दो विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से शुक्रवार को दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकर कर लिया गया। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद की संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों की समीक्षा करेगी। इस समिति के सदस्यों की संख्या 31 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। इससे अधिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। सरकार की ओर से प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में अब शिवसेना (यूबीटी), सीपीआई (एम) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक-एक सदस्य के अलावा भाजपा के दो और समाजवादी पार्टी के एक और सदस्य को शामिल किया गया है।

राहुल पर प्राथमिकी को लेकर प्रियंका का भाजपा पर निशाना

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि इस बात से पता चलता है कि सत्तापक्ष में किस स्तर की हताशा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान सहन नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई ''धक्का-मुक्की'' के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की। राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा के लोगों ने राहुल गांधी जी पर तमाम मामले दर्ज करा रखे हैं। वे नित नई प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और झूठ बोलते हैं। यह उनकी हताशा का स्तर दिखाता है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, यह सरकार 'अदाणी' पर चर्चा से डरती है।

अपराजिता ने प्रियंका को दिया 1984 लिखा बैग गिफ्ट

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने इस बार संसद में अपने बैग के जरिए सभी का ध्यान खींचा। प्रियंका के बाद अब बीजेपी महिला सांसद का बैग चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग भेंट किया। अपराजिता सारंगी बैग को लेकर सदन पहुंची और उन्होंने मीडिया से दावा किया कि वह प्रियंका को गिफ्ट देने के लिए यह बैग लाई हैं। सारंगी के बैग पर 1984 के सिख दंगों की खून के छींटे वाली तस्वीर थी। वीडियो में, प्रियंका गांधी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सारंगी से बैग स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कथित तौर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेताओं की कथित भूमिका की ओर इशारा करने की कोशिश कर रही थीं। मालूम हो कि हाल ही में प्रियंका गांधी जब सदन की कार्रवाई के लिए आई तो उनके कंधे पर एक बैग था जिस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की दुर्दशा को उजागर किया।

धक्का-मुक्की में घायल भाजपा सांसदों की हालत स्थिर

नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में बीते दिन भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई धक्कामुक्की के बाद घायल भाजपा सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनसे मुलाकात की। इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को मिली मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। कुछ रिपोर्ट शुक्रवार को आएंगी। इससे पहले एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दोनों सांसदों को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई धक्कामुक्की के बाद चोटें आई थीं। इस पर भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का दिया। वह सांसद उन पर आ गिरे, जिससे वह घायल हो गए।

हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे। इनेलो मीडिया समन्वयक राकेश सिहाग ने जानकारी देते हुए बताया कि ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में उनके आवास पर शुक्रवार को निधन हो गया है। राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति, चौटाला ने कई अवसरों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें आईएनएलडी में उनके नेतृत्व और राज्य की राजनीतिक दिशा को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। उनकी मृत्यु हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हरियाणा के विकास में चौटाला के योगदान को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। चौटाला परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, हालांकि सभी सदस्य इनेलो और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच विभाजित हैं।

दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

■ हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद का शीतकालीन सत्र

नईदिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र एक तरह से पूरा का पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बार सत्र में कोई खास काम नहीं हो सका। सरकार ने एक देश, एक चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश तो कर दिया लेकिन इसे जेपीसी को विचार के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा वक्फ विधेयक भी टाल दिया गया। इस सत्र में संविधान पर जरूर चर्चा हुई लेकिन वह भी आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रही। सत्र के शुरुआती दिन अडाणी विवाद और अंतिम दिन अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद की भेंट चढ़ गये। इस बीच, संसद परिसर में एक दिन पहले जो कुछ हुआ उससे देश चिंतित नजर आ रहा है क्योंकि बात सिर्फ दो सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को बड़ा नुकसान पहुँचाने की भी है।

इस बीच, संसद परिसर में हुई ''धक्का-मुक्की'' के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मामला दर्ज होने के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस इस घटना में घायल दो सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है और विपक्षी नेता को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां घटना घटी थी। एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि संसद मार्ग थाने में बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में उन पर धक्का-मुक्की के दौरान ''हमला करने और उकसाने'' का

आरोप लगाया गया है। इस धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे।

वहीं संसद की कार्यवाही की बात करें तो आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हुई धक्का-मुक्की की घटना का हवाला देते हुए कहा कि संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार और परिसर के भीतर धरना-प्रदर्शन नहीं करना है और यदि ऐसा होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बिरला ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की धुन बजाने के लिए कहा। 'वंदे मातरम' की धुन के पश्चात उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

वहीं राज्यसभा का 266वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की बैठक दोबारा शुरु हुई तो सदन ने देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक तथा उससे संबंधित एक अन्य विधेयक पर विचार के लिए गठित की जाने वाली समिति में उच्च सदन के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निचले सदन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' पर विचार के लिए बनने वाली संसद की संयुक्त समिति में राज्यसभा के 12 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उच्च सदन से इस समिति में भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी, भुनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, और मुकुल वासनिक, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के पी विल्सन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज और वाईएसआर कांग्रेस के वी विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया।

इस समिति में लोकसभा से जिन 27 सदस्यों को शामिल किया गया उनमें भारतीय जनता पार्टी से पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम रुपाला, अनुराग ठाकुर, विष्णु दयाल शर्मा, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैयजंत पांडा और संजय जायसवाल शामिल हैं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाद्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत को इस समिति का हिस्सा बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और छोटेलाल, तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी, द्रमुक से टी एम सेल्वागणपति, तेलुगु देसम पार्टी से हरीश बालयोगी, शिवसेना (उबाठा) से अनिल देसाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से शांभवी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के के. राधाकृष्णन, राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान और जन सेना पार्टी के बालाशौरी वल्लभनेनी को इस समिति में शामिल किया गया है।

इसके बाद, सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने नेता सदन जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य नेताओं से अपने कक्ष में चर्चा की और उनकी सलाह पर सदन को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। सभापति ने कहा राज्यसभा के 266वें सत्र की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से हुई लेकिन सदन में सदस्यों का जो व्यवहार देखने को मिला, वह अलग ही कहानी बयां करता है। उन्होंने कहा कि सदन में 40.03 प्रतिशत ही कामकाज हो सका। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43.27 घंटे ही प्रभावी कार्यवाही हुई जिसमें दो विधेयक पारित किए गए और भारत-चीन संबंधों पर विदेश मंत्री के का बयान हुआ। इसके बाद धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह का ''आपराधिक तौर पर संपादित'' भाषण दिखाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। बिरला को भेजे पत्र में दुबे ने आरोप लगाया कि गांधी ने सोशल मीडिया, विशेषकर 'एक्स' पर शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण को तोड़-मरोड़ कर उसके ''संपादित'' अंश को साझा करके ''राजनीतिक दिवालियापन'' का एक और उदाहरण पेश किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जनता की भावनाओं को भड़काना तथा संसद और देश की गरिमा को कम करना है। कांग्रेस ने संविधान पर चर्चा के दौरान शाह के भाषण की एक छोटी क्लिप साझा करते हुए उन पर संविधान निर्माता बाबासाहेब बी. आर. आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री ने पार्टी पर उनके भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। दुबे ने कहा कि गृह मंत्री ने अपने भाषण में आंबेडकर के साथ किसी और द्वारा नहीं बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने संसद की कार्यवाही के साथ-साथ शाह के भाषण को भी चतुराई से और संदर्भ से हटकर उद्धृत किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य न केवल संसद की गरिमा को कम करना था, बल्कि शाह को बदनाम करना भी था।

महाराष्ट्र चुनाव में हुआ आतंकी फंड का इस्तेमाल: फडणवीस

नेपाल में बैठक के सबूत मिले, जांच जारी

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में 'आतंकी फंड' के इस्तेमाल की जांच कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय चुनावों में विदेशी दखल के सबूत मिले हैं। फडणवीस ने नासिक जिले के मालेगांव के एक मामले का जिक्र किया, जिसकी जांच जारी है। उन्होंने नेपाल में हुई एक बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें ईवीएम हटाने और चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि विपक्ष ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि देश में अशांति पैदा करने के लिए वे किसे अपने कंधों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। फडणवीस ने कहा, चुनाव जीतने के लिए वोट जिहाद की बात कही गई। आपको 17 मांगें सौंपी गईं और आप चुप रहते हैं। इसी साल मालेगांव में कुछ युवाओं ने पुलिस से उनके खातों में 114 करोड़ रुपये की बेनामी रकम जमा होने की शिकायत की थी। आरोपी सिराज मोहम्मद ने मालेगांव में नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में 14 खाते खोलने के लिए 14 व्यक्तियों के आधार और पैन विवरण का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके से जमा किए गए 114 करोड़ रुपये सिराज मोहम्मद को और 21 अन्य खातों में भेज दिए गए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मालेगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि 21 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें 201 खातों में 1,000 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। फडणवीस ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये में से 600 करोड़ रुपये दुबई भेजे गए, जबकि 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया। फडणवीस ने कहा कि इस साल 15 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बैठक हुई थी, जिसमें (राहुल गांधी के नेतृत्व वाली) भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने वाले कुछ संगठन शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के विरोध और महाराष्ट्र और भाजपा शासित राज्यों में मतपत्रों का इस्तेमाल शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मेलबर्न और सिडनी में होने वाले चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। इनमें ओपनर नाथन मैकस्वीनी का नाम शामिल है, जो शुरुआती तीनों टेस्ट में फेल रहे थे। मैकस्वीनी को डेविड वॉर्नर के संन्यास लेने के बाद उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया था। हालांकि, वह नहीं चले और अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 19 वर्षीय सैम कोंस्टास को स्क्वॉड में शामिल किया है। कोंस्टास ने एडिलेड में गुलाबी गेंद के टेस्ट से पहले कैनबरा में टीम इंडिया के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश के लिए खेलते हुए अभ्यास मैच में शतक लगाकर कई लोगों को प्रभावित किया था।

मैकस्वीनी का टीम से बाहर होना एकमात्र बड़ा बदलाव नहीं है। मार्की तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड को ब्रिसबेन टेस्ट में चोट लगी थी जिसके कारण वह उस टेस्ट के अंतिम दो दिन भी मैदान पर नहीं उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सीन एबॉट, झाय रिचर्डसन और ब्यू वेबस्टर को भी सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने आधिकारिक बयान में कहा, टीम के पास कई विकल्प हैं और इससे हमें सीरीज के बाकी बचे मैचों के लिए परफेक्ट-11 बनाने में मदद मिलेगी। सैम को पहली बार टेस्ट टीम में कॉल-अप मिला है। उनकी बल्लेबाजी की शैली अंतर प्रदान करती है और हम उनके खेल को और विकसित होते देखने के लिए उत्सुक हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम- पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, सैम कोंस्टास, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, ब्यू वेबस्टर, सीन एबॉट, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, झाय रिचर्डसन, एलेक्स कैरी, स्कॉट बोलैंड और जोश इंगलिस।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1176 अंक टूटा निफ्टी 23,600 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेंशन में बेंचमार्क इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। शेयर बाजर में गिरावट का यह लगातार पांचवा दिन था। 30 शेयरों वाला, बीएसई सेंसेक्स 1176.46 अंक या 1.49 प्रतिशत की भारी गिरावट लेकर 78,041.59 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 77,874.59 और 79,587.15 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 364.20 अंक या 1.52% प्रतिशत टूटकर 23,587.50 पर बंद हुआ। निफ्टी50 में आज 23,537.35 और 24,065.80 के रेंज में कारोबार हुआ।

भारतीय ईवी उद्योग 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का होगा

नई दिल्ली। भारतीय ईवी उद्योग अगले पांच वर्षों में तेज रफ्तार से बढ़ने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले दिनों में भारत में ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी की पुष्टि की। और अनुमान लगाया कि यह लाखों नौकरियां पैदा करने के साथ ईवी की बिक्री कई गुना बढ़ सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अभी भी शुरुआती चरण में है और कुल वाहन बिक्री में इसकी बाजार हिस्सेदारी एकल अंकों में है। इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 18 लाख से ज्यादा ईवी पंजीकृत किए गए, जो सभी सेगमेंट में कुल वाहन बिक्री का 10 प्रतिशत से भी कम है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारतीय ईवी उद्योग 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। जो मौजूदा 4.50 लाख करोड़ रुपये से लगभग पांच गुना का लक्ष्य है।

बिहार में अबतक 1.80 लाख करोड़ का निवेश समझौता

पटना। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का शुक्रवार को दूसरा दिन है। दो दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इनवेस्टर्स समिट में देश-विदेश की कंपनियों के 850 प्रतिनिधि आए हैं। आज 350 से ज्यादा कंपनी बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रही। इस सबमिट के जरिए बिहार में करीब एक लाख 80 करोड़ का निवेश हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में तीन गुना है। इनमें सीमेंट, फुटवियर, टेक, इथेनॉल समेत अन्य सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। सन पेट्रोकेमिकल्स 36400 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। यह अब तक सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी का दावा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं भारत सरकार की पीएसयू एनएचपीसी और एसजेवीएन 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट में निवेश करेगी।

नए साल में होंडा कार की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी

नईदिल्ली। होंडा कार्स इंडिया ने अगले साल जनवरी से अपने सभी मॉडल की कीमतों में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की शुक्रवार को घोषणा की। कंपनी घरेलू बाजार में अमेज, सिटी और एलिवेट जैसे मॉडल बेचती है। होंडा कार्स इंडिया के उपाध्यक्ष (विपणन एवं बिक्री) कुणाल बहल ने कहा कि वाहन विनिर्माता कंपनी जनवरी 2025 की शुरुआत से अपने मॉडलों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी। बहल ने कहा, '' कच्चे माल की लागत और लॉजिस्टिक्स में निरंतर वृद्धि के कारण इसका छोटा सा भार नए साल से मूल्य संशोधन के जरिये ग्राहकों पर डाला जाएगा।'' मारुति सुजुकी, हुंदै और टाटा मोटर्स सहित विभिन्न कार विनिर्माता कंपनियां पहले ही जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी हैं।

भारतीय कपड़ा उद्योग के अच्छे दिन

डॉ. सुरजीत सिंह

शेख हसीना के निष्कासन के बाद पड़ोसी बांग्लादेश गहरे राजनीतिक संकट में फंस चुका है। अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को दरकिनार कर भारत के साथ टकरावपूर्ण रुख अपना रहा है। बांग्लादेश की कमान अब सेना के हाथ में है। कट्टरपंथियों के प्रभाव के कारण अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा ने बांग्लादेश को अस्थिरता के दौर में पहुंचा दिया है। जसीमुद्दीन रहमानी जैसे खतरनाक आतंकवादी की रिहाई के बाद बांग्लादेश भी न सिर्फ पाकिस्तान की तरह दिवालिया होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि आर्थिक पतन के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहा है।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला कपड़ा उद्योग अस्थिर कानून-व्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है। कई कंपनियां देश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण अपना परिचालन बंद करने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था। अमेरिका एवं यूरोपीय बाजार में बांग्लादेश के कपड़ों की बहुत मांग थी। पश्चिम को जिस पैमाने पर और जैसा उत्पाद चाहिए, उसमें बांग्लादेश ने विशेषज्ञता हासिल कर ली थी।

यूरोपीय बाजार में भारत के मुकाबले बांग्लादेशी उद्यमियों की पहुंच अधिक थी। बांग्लादेश का फलता-फूलता कपड़ा उद्योग देश की जीडीपी में 11 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान करता था एवं कुल निर्यात में कपड़ा निर्यात का योगदान 80 प्रतिशत था। बांग्लादेश ने साल 2023 में लगभग 47 अरब डॉलर से अधिक का टेक्सटाइल निर्यात

किया था। इस साल इसके 50 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद थी, लेकिन, देश में फैली हिंसा ने कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और लगातार काम बंद होने से बांग्लादेश निर्यात ऑर्डर पूरा करने की स्थिति में भी नहीं है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई है, बल्कि कोरोना काल के बाद से ही बांग्लादेश में निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ता घाटा, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा का अवमूल्यन, बढ़ती आय असमानता, बढ़ते गैर निष्पादित ऋण, अपेक्षित सुधारों की कमी आदि के कारण न सिर्फ बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बल्कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी घटने लगा था।

राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क बेक्सिंपों पर ताला लग चुका है। इसके साथ ही 170 बड़ी टेक्सटाइल फैक्टरियां भी बंद होने के कगार पर हैं। बांग्लादेश का तानाबाना बिखरने के कारण वहां कार्य करने वाले लगभग लाखों मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। कई वैश्विक खिलाड़ी, जो हिंसा के कारण घाटे का सामना कर रहे हैं, अब भारत में परिचालन स्थानांतरित करने और भारतीय निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि चीन प्लस वन नीति के कारण अमेरिका और यूरोपीय बाजार चीन के साथ जाने के बजाय भारत को अधिक वरीयता देते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड में 2020 में चीन का निर्यात 27 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 19 प्रतिशत ही रह गया है। साल 2023 में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में भारत की हिस्सेदारी छह प्रतिशत थी, जो अक्तूबर, 2024 तक बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है। इंग्लैंड को किए जाने वाले कपड़ा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023 में पांच प्रतिशत थी, जो बढ़कर अक्तूबर, 2024 तक छह प्रतिशत पर आ गई है। बांग्लादेश के तनावपूर्ण हालात के कारण सरकार उनको भारत में परिचालन के अवसर उपलब्ध करवाकर देश के कपड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। इससे वैश्विक कपड़ा सप्लाई चेन में भारत की पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी। इससे न केवल अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आएगा, बल्कि लाखों नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। भारत में कपड़ा उद्योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज भारत इस उद्योग के माध्यम से ब्रांड इंडिया के रूप में वैश्विक लीडर के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है।

विकसित भारत बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका महत्वपूर्णः रमेन डेका

भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। **भारत सबसे तेजी से बढ़ती** हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकि प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विचार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने उदबोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकि और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं।

श्री डेका ने कहा कि सम्मेलन का विषय भौतिक विज्ञान में उभरते रूझान इस उभरते क्षेत्र में अपने ज्ञान पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर वैज्ञानिक जांच और नवाचार के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक इस सम्मेलन में एक साथ उपस्थित हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है। यह अनुसंधान नवाचार और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरक का काम करेगी। सम्मेलन युवा और नवोदित वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के माध्यम से अपने संभावित शोध को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। स्नातकोत्तर छात्रों को शामिल करना और उनकी पोस्टर प्रस्तुतियां इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ज्ञान, विचारों और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण शोध और अभिनव समाधानों के लिए यह सम्मेलन उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर स्वागत भाषण रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद ने दिया। प्रोफेसर कल्लोल घोष ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

पीएम मोदी से सपरिवार मिले सांसद बृजमोहन

रायपुर । सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को अपने परिवार के साथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस सौजन्य मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अग्रवाल परिवार के सदस्यों से उनके हालचाल पूछे और बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया।

भेंट के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुलाकात को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सादगीपूर्ण और दूरदर्शी व्यक्तित्व से हमें नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। यह हमारे परिवार के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है।इस मुलाकात में प्रधानमंत्री की सहजता और अपनापन परिवार के हर सदस्य के लिए विशेष अनुभव रहा। बच्चों को मोदी जी के साथ बिताया समय खासा प्रिय लगा, और परिवार ने इसे अपनी स्मृतियों में सहेजने वाला पल बताया।

धान के उठाव में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था सहित कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को विक्रय में सहुलियत प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में धान खरीदी सुव्यस्थित हो तथा किसानों को सरलता के साथ बारदाना उपलब्ध हो इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 63.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।

धान खरीदी के एवज में राज्य 13.19 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 14058 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी है। धान के उठाव में तेजी लाने के प्रदेश के

लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर निस्वार्थ भाव से काम करें: जायसवाल

रायपुर । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस के आडिटोरियम में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। शुक्रवार को शुरू हुई ये समीक्षा बैठक दो दिनों तक चलेगी। समीक्षा बैठक के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि सभी अधिकारी एवं चिकित्सक आम जन के स्वास्थ्य को देखते हुए निस्वार्थ भाव से काम करें।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार करने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर मे 200 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायपुर के मेकाहारा में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन का 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर, चार नवीन मेडिकल कालेजों के लिए 1 हजार 20 करोड़ का ई टेंडर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से एक वर्ष के भीतर 8 सौ से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, राज्य में एमबीबीएस की हिन्दी में पढ़ाई जैसे निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है। जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन के जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। विभागीय समीक्षा बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ ही जिलों से आए अधिकारी भी उपस्थित थे।

सीएम साय से मिले विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आये मुंगेली जिले के बच्चे

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर में मुंगेली जिले से विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आये बच्चों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने बच्चों से बहुत ही आत्मीयता से मुलाकात की और विनोदपूर्वक बच्चों से पूछा- कौन-कौन आएंगे राजनीति में। मुख्यमंत्री साय का सवाल सुनकर कई बच्चों ने हाथ उठा कर राजनीति में आने की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब मन लगाकर पढाई करने और शैक्षणिक भ्रमण के अवसर का लाभ उठाने की सीख दी।

आज मुंगेली ज़िले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, परसिया और संस्कार विद्या मंदिर, सकेल के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। मुख्यमंत्री साय को बच्चों ने बताया कि अपने रायपुर भ्रमण के दौरान वे पुरखौती मुक्तांगन, स्वामी विवेकानंद विमानतल, मंत्रालय महानदी भवन, इंद्रावती भवन और बंजारी मंदिर का भी भ्रमण करेंगे। विधानसभा भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।इस अवसर पर विधायक धरम लाल कौशिक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसिया और

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

कलेक्टर ने ली गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक

रायपुर। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 गरिमापूर्ण आयोजित करने के लिए कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग के उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार करें। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ध्वजारोहण, मंच, पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम, भाग लेने वाली टुकड़ियों का निर्धारण एवं रिहर्सल, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों तथा उत्कृष्ट झांकी को पुरस्कार वितरण के साथ ही कार्यक्रम के उद्घोषक का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पार्किंग एवं ट्रेफिक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया। पुलिस परेड ग्राउंड में साफ-सफाई, अस्थाई शौचालय इत्यादि की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ 24 जनवरी को रिहर्सल का भी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

उद्योग मंत्री कोरबा में करेंगे प्री पेड बूथ का शुभारंभ

रायपुर । वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन 21 दिसम्बर को कोरबा रेलवे स्टेशन परिसर में प्रीपेड बूथ का शुभारंभ और दो वार्डो में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में 1.42 करोड़ की लागत से सात वार्ड में होने वाले 12 विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री देवांगन दोपहर 2:30 बजे स्याहीमुड़ी दर्री, गांधी चौक के पास आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में चार वार्ड क्रमशः 43, 45, 46 और 50 में 75 लाख की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन कर शिलापट्टी का अनावरण करेंगे। तत्पश्चात साढ़े तीन बजे आंबेडकर चौक अयोध्यापुरी में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद वे दोपहर साढ़े 4 बजे रेलवे स्टेशन कोरबा में प्री पेड बूथ का शुभारंभ करेंगे। शाम 5 बजे सीतामणी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में तीन वार्ड क्रमशः 05, 06 और 07 में कुल लागत 67 लाख के कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इसके पश्चात विकास नगर कला मंच कुसमुंडा में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात् वैशाली नगर, कुसमुंडा में सोहित राम यादव परिवार के दशगात्र कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात करेंगे।

सगनीघाट-सिल्लीघाट पुल पर आवागमन जल्द शुरू होगा

रायपुर । दुर्ग जिले के सगनीघाट और सिल्लीघाट के बीच शिवनाथ नदी पर निर्माणाधीन नए पुल का काम पूर्ण होने के कगार पर है। 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे पुल का 95 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। अभी पुल के दोनों ओर सीसी रोड निर्माण का काम प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में पुल के ऊपर बीटी वर्क के बाद पुल आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा।

लोक निर्माण विभाग द्वारा दुर्ग-धमधा मार्ग को जालबांधा-खैरागढ़ मार्ग से जोड़ने वाली सड़क में शिवनाथ नदी पर सगनीघाट और सिल्लीघाट के बीच 400 मीटर लंबे नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के 12 गांवों की करीब 20 हजार आबादी के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर जिला मुख्यालय दुर्ग, विकासखंड मुख्यालय धमधा, जालबांधा एवं खैरागढ़ की ओर आने-जाने वालों को फायदा होगा। धमधा, ननकट्ठी, सगनी, लिटिया, बोरी और सिल्ली जैसे कई गांवों के लोग अब नदी के उस पार के गांवों में बारहों महीने निर्बाध आवागमन कर सकेंगे। इससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन 2 जनवरी तक

रायपुर। किसी घटना विशेष में उनके अदम्य साहस के लिए प्रत्येक वर्ष पांच बालक-बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत पांच बालक-बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को दिये जाने वाले राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।आवेदक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में 2 जनवरी 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए बालक-बालिका की आयु-घटना दिनांक को अधिकतम 18 वर्ष तक होनी चाहिए। वीरता कार्य 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य की होनी चाहिए। यह पुरस्कार किसी भी बालक-बालिका को केवल एक ही बार प्राप्त हो सकेगा। प्रविष्टियों में बालक या बालिकाओं का पूर्ण परिचय बालक-बालिकाओं द्वारा किसी घटना विशेष में अदम्य साहस, शौर्य एवं बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी उल्लेखित हो। आवेदक को यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। साथ ही समाचार पत्र-पत्रिका की कतरन ,पुलिस डायरी जिसमें घटना का विवरण दर्शित हो साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बालक-बालिका के दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना होगा।

राहुल पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

रायपुर । केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर

के ऊपर आपत्ति जनक टिप्पणी एवं राहुल गांधी के ऊपर झूठी एफआईआर के विरोध मे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। घड़ी चौक स्थित अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथो मे बाबा साहेब की फोटो एवं तख्ती लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता घंटो तक बैठे रहे।प्रदर्शन मे पहुचे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब पर दिया गया बयान बेहद अपमान जनक है। संविधान और दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले अमित शाह ने करोड़ो भारतीयो की भावनाओ का अपमान किया है।पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बाबा साहब के बारे मे अमित शाह द्वारा दिया गया बयान बेहद निंदनीय है।

इस कृत्य के लिए उनको देश से माफी मांगनी

युवा महोत्सव मड़ई 2024

गीत, नृत्य एवं नाटिकाओं ने बटोरीं दर्शकों की तालियां

एकांकी, एकल अभिनय, रंगोली एवं पेंटिंग ने मन मोह लिया

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित सांस्कृतिक युवा महोत्सव मड़ई 2024 के दूसरे दिन आज यहां कृषि महाविद्यालय रायपुर के विभिन्न सभागृहों एवं प्रेक्षागृहों में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एकल अभिनय, तात्कालिक भाषण, ऑन दी स्पॉट पेंटिंग, एकांकी, समूह गायन, कोलाज मेकिंग, मिमिक्री, भाषण, समूह गायन (भारतीय), लोक एवं आदिवासी नृत्य आदि प्रतियोगिताओं में आकर्षक एवं भावप्रवण प्रस्तुतियां दी गई।

इन विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत दी गई प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, प्रौद्योगिकी विकास, नारी सशक्तिकरण, दहेज उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, असमानता एवं अस्पृश्यता निवारण जैसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को उकेरा गया। युवा कलाकारों ने अपनी संप्रेषणीयता, भावाभिनय, संवाद कौशल, रेखांकन कौशल आदि के माध्यम से दर्शकों को दिल जीत लिया तथा खूब तालियां बटोरीं।

मड़ई 2024 के अंतर्गत आयोजित समूह नृत्यों की रंगा-रंग प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। विभिन्न प्रतिभागियों ने आकर्षक रंगोली, मेहंदी, पोस्टर मेकिंग आदि के माध्यम से अपने भावों को रूपाकार दिया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, सांस्कृतिक प्रभारी एवं अयोजन सचिव डॉ. बी.पी. कतलम विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रभारी तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायकगण उपस्थित थे।

राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 21 दिसंबर को किसान सम्मेलन एवं कृषि संगोष्ठी

कृषक उन्नति योजना से लाभान्वित कृषकों का होगा सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर को राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचाना है।

किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाएगा। कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके साथ ही, समर्थन मूल्य और आदान सहायता को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 3100 प्रदान किया जा रहा है।

बीते वर्ष छत्तीसगढ़ ने 145 लाख मेट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की थी। इस साल खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन के कारण 160 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में धान का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.